facebook.com/ thebharatshri
twitter.com/ thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 30 मार्च 2026 ● वर्ष 7 ● अंक 37 ● मूल्यः 5 रुपए

बच्चों की पढ़ाई क्यों बनी...

सद्गुरु वाणी

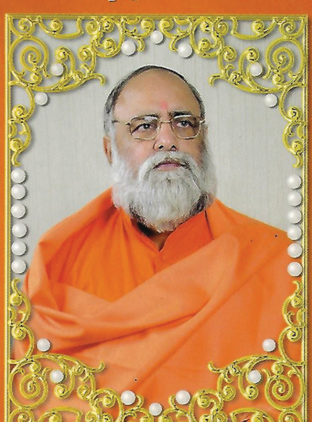

विश्व भर में होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम केवल प्रभु की कृपा से संभव होते हैं। इसका आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता।

●

परमात्मा की नजर में सभी भाई-बहन बराबर हैं। परमात्मा जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय से पार है। हमें सभी भाई-बहनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए।

●

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

कृपा वचन

जब मन शांत होता है, तब ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता है।

●

जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा।

●

शिक्षा कमाने का जरिया ही नहीं, सोचने का नजरिया भी देती है।

●

कोई हमारी निंदा करे या प्रशंसा करे दोनों ही हमारे लिये अच्छे हैं, क्यूंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर।

नक्सलवाद पर देश की आखिरी लड़ाई

विकास और विचारधारा के बीच संघर्ष

लोकसभा में अमित शाह ने स्पष्ट किया -हथियार उठाने वालों को भुगतना होगा, आदिवासियों के लिए विकास ही असली सुरक्षा

@ भारतश्री ब्यूरो

लोकसभा में मंगलवार को नक्सलवाद पर चर्चा ने संसद को और देश के नागरिकों को एक बार फिर झकझोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि देश में हथियार उठाकर व्यवस्था को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। "जो लोग पूरी व्यवस्था को नकारकर हथियार उठाते हैं, उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी," शाह ने जोर देकर कहा।शाह की बातें केवल आंकड़ों और नीतियों तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने भावनाओं और ह्यूमन एंगल को सामने रखते हुए बताया कि किस तरह भोले-भाले आदिवासियों को दशकों तक अंधेरे में रखा गया। अमित शाह ने आगे कहा कि वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आदिवासियों को बहकाया।

आदिवासियों की पीड़ा और 60 साल का इंतजार

अमित शाह ने विस्तार से बताया कि कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्षों में 60 साल तक शासन किया और इस दौरान आदिवासियों तक बुनियादी विकास की पहुंच नहीं हुई। आप पूछ सकते हैं कि इतने सालों में आदिवासियों के गांवों में घर, स्कूल, मोबाइल टावर क्यों नहीं पहुंचे? इसका जवाब साफ है यह जानबूझकर रोका गया। और अब जब सरकार उन्हें विकास के रास्ते पर ले जा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। अपने गिरेबान में झांककर देखिए, जो लोग नक्सलवाद की वकालत करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि यह सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ? वे केवल नीति और कानून के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन जीवन की हकीकत में बात कर रहे थे, जिनकी जान, उनकी सुरक्षा और भविष्य लंबे समय तक लुप्त होते रहे।

नक्सलवाद का असली कारण विचारधारा

शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। ये आदिवासियों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनका मकसद विकास नहीं बल्कि सत्ता है। इस विचारधारा को आदिवासियों में फैलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश होती रही है।उन्होंने CAPF के जवानों, कोबरा कमांडो, CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि यह बड़ी घटनाएं केवल उनके साहस और मेहनत की वजह से संभव हुईं। साथ ही उन्होंने वहां के आदिवासियों का भी श्रेय दिया, जिन्होंने सहयोग करके उग्रवाद को खत्म करने में मदद की।हजारों युवा मारे गए, जवान शहीद हुए और आदिवासियों की पीड़ा बढ़ी। शाह ने कहा कि 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर था, वहां कानून का शासन नहीं था। 12 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे।

देश में नक्सलवाद के पीछे कोई विकास का मुद्दा नहीं है, यह एक विचारधारा है। १२ वर्षों में हमारी सरकार ने आदिवासियों तक घर, स्कूल, मोबाइल टावर पहुँचाए हैं, रेड कॉरिडोर खत्म किया है और सुरक्षा सुनिश्चित की है। जो लोग हथियार उठाते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह केवल कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का विषय है।

अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री)

हम मानते हैं कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसे केवल सैन्य और प्रशासनिक कदमों तक सीमित नहीं किया जा सकता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सामाजिक योजनाओं का विस्तार पहले से ही अहम था। पिछले ६० सालों में कुछ क्षेत्रों में विकास की कमी रही, और इसे नजरअंदाज करके केवल सुरक्षा उपायों को ही समाधान बताना उचित नहीं है। वेलफेयर और सामाजिक सुधार को भी साथ लेकर चलना जरूरी है।

महुआ मोइत्रा (TMC सांसद)

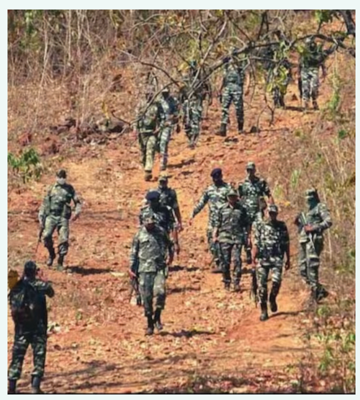

- १२ साल में कानून और विकास ने हिंसा घटाई।
- १०,००० युवाओं की जान बचाने में सरकार की पहल।
- नक्सलवाद केवल विकास की कमी नहीं, विचारधारा का असर।
- सत्ता बंदूक से नहीं, नीति और जागरूकता से।
- आदिवासी भागीदारी ने रेड कॉरिडोर को शांत किया।

पिछले 12 साल में क्या बदला

शाह ने मोदी सरकार के 12 वर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह देश की आंतरिक सुरक्षा, विकास और कानून व्यवस्था में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A हटाने, राम मंदिर निर्माण, CAA कानून, और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे फैसले देश को मजबूत बनाने वाले थे।शाह ने जोर देकर कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का छात्र इसकी रेटिंग करे, तो वह नक्सलमुक्त भारत को पहले नंबर पर रखेगा। हमने ढेर सारी योजनाएं बनाई, लेकिन कई वर्षों तक विपक्ष और अन्य कारकों ने उन्हें लागू नहीं होने दिया।

विपक्ष ने भी रखी अपनी राय

संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी अपनी राय रखी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज देश राइटविंग आतंकवाद और एनर्जी क्राइसिस जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

MN DIVINE
ORDER ALL TYPES OF :
• POOJA SAMAGRI,
• AYURVEDIC MEDICINE
• AND PRATIMA.
NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM
ORDER NOW
https://mndivine.com/
HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

दिल्ली मेट्रो के नियम बदलने की तैयारी

जुर्माने बढ़ेंगे, महिला कोच में प्रवेश पर कड़ी सजा

@ सौम्या चौबे

दिल्ली में मेट्रो यात्रा अब पहले से थोड़ी महंगी नहीं, बल्कि नियमों के लिहाज से अधिक सख्त होने वाली है। शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में जन विश्वास विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक के जरिए दिल्ली मेट्रो से जुड़े कई नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। अगर यह विधेयक पास हो जाता है, तो मेट्रो में अनुशासनहीन व्यवहार करने वाले यात्रियों पर पहले से कहीं अधिक कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।विधेयक के मुताबिक, मेट्रो के फर्श पर बैठना, डिब्बे में लिखना, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करना, या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री ले जाना अब महंगा पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य साफ है- मेट्रो यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और सभी के लिए सम्मानजनक बनाना।

नए नियमों के प्रमुख बदलाव

वर्तमान में मेट्रो में यात्रियों द्वारा किए जाने वाले कई अनुशासनहीन कार्यों पर केवल 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। इनमें नशे में यात्रा करना, झगड़ा करना, फर्श पर बैठना, थूकना, उपद्रव करना, या आपत्तिजनक सामग्री ले जाना शामिल है। नया प्रस्तावित नियम इन्हें बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने की बात करता है। इसके अलावा, मेट्रो कोच पर कुछ लिखने या उसे हटाने से मना करने पर फिलहाल 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। नया विधेयक इस प्रावधान को पूरी तरह बदल देता है। अब ऐसे मामलों में अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की सजा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। विशेष रूप से, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करने वाले पुरुषों पर अब अधिकतम 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौजूदा समय में केवल 250 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल का प्रावधान है। इस बदलाव से महिला यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।

मेट्रो में अनुशासन और सुरक्षा

दिल्ली मेट्रो सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह शहर की धड़कन भी है। लाखों लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नियमों का पालन जरूरी है।शहर के कई मेट्रो स्टेशन हमेशा भीड़भाड़ वाले होते हैं। भीड़ में अनुशासनहीन व्यवहार न केवल यात्रा को असुविधाजनक बनाता है, बल्कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा की समस्या भी खड़ी करता है। इस कारण नए नियमों में आर्थिक दंड को बढ़ाना और जेल की सजा को हटाना दोनों ही कदम यात्रियों की सुरक्षा और समय की बचत के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

पेनाल्टी से अनुशासन कायम

मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में अपराधियों या अनुशासनहीन यात्रियों को पकड़ने और जेल तक भेजने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। वहीं, आर्थिक दंड तुरंत लगाया जा सकता है और इसका असर भी तेज दिखाई देता है।जितिन प्रसाद ने बताया कि विधेयक का मकसद आपराधिक प्रवधानों को आसान और प्रभावी आर्थिक दंड में बदलना है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई यात्री नियम तोड़ता है, तो उसे तत्काल आर्थिक जुर्माने का सामना करना होगा। इससे मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना आसान होगा।

क्या बदलेगा मेट्रो का अनुभव?

अगर यह विधेयक पास हो जाता है, तो दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के अनुभव में कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं।फर्श पर बैठना या कोच पर लिखना – अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना। इसका मतलब है कि मेट्रो की सफाई और स्वच्छता को लेकर अब यात्रियों में अधिक सतर्कता आएगी। महिला कोच में प्रवेश पुरुषों के लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना। यह कदम महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा।आपत्तिजनक सामग्री -अगर कोई यात्री मेट्रो में असुरक्षित या आपत्तिजनक वस्तुएं लेकर आता है, तो जुर्माना बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगा।नशे में यात्रा या उपद्रव -अब जुर्माना बढ़कर 2500 रुपये। इससे भीड़ में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी।इन सभी बदलावों का लक्ष्य साफ है -मेट्रो को एक सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित परिवहन प्रणाली बनाना।

यात्रियों की प्रतिक्रिया

दिल्ली के मेट्रो यात्री भी इन बदलावों को लेकर उत्साहित हैं। कई लोग कहते हैं कि "कुछ लोग मेट्रो में अनुशासनहीन होते हैं, और इससे यात्रा करना असुविधाजनक हो जाता है। जुर्माने बढ़ाने से ऐसा व्यवहार कम होगा। वहीं, कुछ लोग इसे थोड़े सख्त कदम के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि जुर्माना बढ़ाना एक प्रभावी तरीका है, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि मेट्रो प्रशासन इसे सही और निष्पक्ष तरीके से लागू करे।केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक "सिर्फ दंड के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए" लाया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आर्थिक दंड के जरिए मेट्रो प्रशासन आसानी से अनुशासन कायम कर सकेगा, और यात्रियों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 में यह बदलाव सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नया विधेयक पास होने के बाद यात्रियों को साफ-सुथरी, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगा।दिल्ली मेट्रो, जो लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, अब और अधिक सुरक्षित और अनुशासित होने जा रही है। नए नियम और जुर्माने न केवल यात्रियों को सजग करेंगे, बल्कि मेट्रो के सफाई, सुरक्षा और महिला यात्रियों की सुरक्षा को भी मजबूत बनाएंगे। जहां एक तरफ यह बदलाव अनुशासन को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर यह यात्रियों को भी यह समझने में मदद करेगा कि सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन बनाए रखना सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन दिल्ली में अरेस्ट

दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।पुलिस के मुताबिक, शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था। यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था।साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में लोन को गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था।

छोटे सिलिंडर यूज करने वालों के लिए आ रहा है नया नियम

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है जिसके चलते महानगरों में गैस सिलिंडर की किल्लत बढ़ गई है।

इस बीच केंद्र सरकार आम लोगों खासकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही 5 किलो का छोटा एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, जिससे बिना गैस कनेक्शन वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

दिल्ली में गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन सर्टिफिकेट

गौसंरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र वितरित किए। साथ ही सीएम गुप्ता द्वारा आधुनिक बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।सरकार की ओर से प्रथम चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इन गौशालाओं में निराश्रित गौमाता की देखभाल, संरक्षण और उनके समुचित संवर्धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

बिना तलाक लिए लिव-इन में नहीं रह सकते, कानूनी सुरक्षा नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

@ अभिषेक चौबे

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम टिप्पणी की है, जो समाज और कानून दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, बिना तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकते। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंजू और उनके साथी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दी। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे पति-पत्नी की तरह एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा है। उन्होंने अदालत से पुलिस और अन्य पक्षकारों को उनके "शांतिपूर्ण जीवन" में दखल न देने का निर्देश देने की मांग की थी।

पहले तलाक लें, फिर लिव-इन

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि सक्षम अदालत से तलाक प्राप्त किए बिना, लिव-इन संबंध में रहने वाले याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई रिट या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता किसी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो वे संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी प्रार्थना पत्र की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदालत के मुताबिक, याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा हैं और बिना तलाक के उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना न केवल अवैध है, बल्कि सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं के भी खिलाफ है। सरकारी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इस तरह की याचिकाओं को मंजूरी देना संविधान के और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

निजी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार

अदालत ने अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि दो वयस्क व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और उनके माता-पिता तक उनके संबंधों में दखल नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है; इस पर कुछ पाबंदियां लागू होती हैं। न्यायमूर्ति ने कहा, "एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार शुरू होता है। एक पति या पत्नी को अपने जीवन साथी के साथ रहने का कानूनी अधिकार है, और निजी स्वतंत्रता के नाम पर उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षाओं तक सीमित नहीं है। यह अधिकार दूसरे व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों से टकराए बिना ही मान्य है।

लिव-इन संबंध और कानून

लिव-इन रिलेशनशिप को भारत में पूरी तरह कानूनी मान्यता 2006 के बाद दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दो वयस्क व्यक्तियों का आपसी सहमति पर आधारित संबंध अपराध नहीं है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि यह मान्यता केवल उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं या जिनका पूर्व संबंध समाप्त हो चुका है। शादीशुदा व्यक्ति का बिना तलाक के किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना न केवल कानून के दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी स्वीकार्य नहीं माना जाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि ऐसे मामलों में लिव-इन के नाम पर सुरक्षा की मांग करना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संभव नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की स्थिति और पुलिस की भूमिका

अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता किसी प्रकार के उत्पीड़न, धमकी या हिंसा का सामना कर रहे हैं, तो वे विस्तृत प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी इस प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह कदम याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, लेकिन अदालत ने साफ किया कि यह सुरक्षा केवल उनके कानूनी अधिकारों और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में ही लागू होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित

वितरित किए 69,794 स्मार्टफोन और आधुनिक उपकरण

@ अभिषेक चौबे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें 69,794 स्मार्टफोन, 1,33,282 स्टेडियोमीटर, 10,553 इंफॉन्टोमीटर और 58,237 वजन तौलने की मशीनें वितरित कीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि सरकार उनका सम्मान करने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले चार साल से उनका प्रयास रहा है कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास एक स्मार्टफोन हो। उनका मानना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मेहनत करती हैं, उसका रियल टाइम डेटा समय पर नहीं मिल पाने की वजह से प्रदेश की रैंकिंग पर असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन वितरण और उनके उपयोग में प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल सेवा का केंद्र बन सकें और बच्चों की देखभाल में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ सके।

CM योगी ने कि पिछली सरकार की आलोचना

सीएम योगी ने पिछली सरकार की पोषण वितरण प्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पोषाहार के वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया को दिया गया था। उन्होंने कहा, "जब सरकार बनी तो मैं भौचक रह गया। यह तो शराब माफिया है, इसका यहां क्या काम। लेकिन सब काम वही करता था। पोषाहार कहीं पहुंचता था, कहीं नहीं। गुणवत्ता इतनी खराब थी कि बच्चों की स्थिति गंभीर थी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बच्चों के पोषाहार पर डकैती डालने का काम करते थे, उनकी जगह आज ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ चयन हो रहा है। उनका यह बयान यह साफ करता है कि वर्तमान सरकार बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर गंभीर है।

गरीब की पीड़ा को समझना आवश्यक

सीएम योगी ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो भी सुविधा दी जा रही है, उसका उद्देश्य बच्चों और गरीब परिवारों तक सेवाओं की गुणवत्ता पहुंचाना है। उन्होंने कहा, "गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा, वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वे इस पीड़ा से नहीं जुड़ सकते। उनके लिए सबकुछ केवल उनके परिवार के लिए चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्मार्टफोन और आधुनिक उपकरण वितरण का लक्ष्य आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल सेवा केंद्र बनाना है। इससे रियल टाइम डेटा मिल सकेगा, पोषण और स्वास्थ्य के रिकॉर्ड समय पर अपडेट होंगे, और बच्चों की स्थिति बेहतर तरीके से ट्रैक की जा सकेगी।

स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र और सम्मानजनक मानदेय

सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होंगे तो कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट और सम्मानजनक होना चाहिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि वे अतिशीघ्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा, "जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, सरकार उसके साथ खड़ी होकर उसे सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी। जब प्रदेश संकट में था, तब भी आप लोग घर-घर स्क्रीनिंग का काम कर रहे थे। यही मेहनत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।सीएम ने यह भी बताया कि स्मार्टफोन वितरण के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को उनके काम में डिजिटल दक्षता भी दी जाएगी। इससे उनका काम और अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा।

सीएम योगी ने कहा कि अप्रैल से प्रदेश में सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक विशेष कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। उन्होंने पिछली व्यवस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि पहले आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में भारी कटौती और शोषण होता था। सरकार से जितना पैसा आता था, वह कर्मचारी को पूरा नहीं मिलता था। कुछ हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता था। अब हमने इसे पूरी तरह पारदर्शी और नियमित किया है।

सोनभद्र के जंगलों की तक़दीर 13 अप्रैल को होगी तय

पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट या हरा-भरा जंगल – कौन जीतेगा?

@ शोभित यादव

सोनभद्र में 17,000 करोड़ रुपये के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई आज नहीं हो सकी। इसके पीछे मुख्य वजह वकीलों की स्ट्राइक बताई जा रही है। अब सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल 2026 तय की गई है ।यह प्रोजेक्ट कई लोगों के लिए आशा और चिंता का मिश्रण बन चुका है। एक ओर इसे राज्य और देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह खतरे की घंटी है।

ग्रीन कॉरिडोर और वन्य जीवन पर खतरा

गुप्त काशी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। ट्रस्ट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण सोनभद्र जिले के बड़े ग्रीन कॉरिडोर को भारी नुकसान हो सकता है ।इस क्षेत्र में कई औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो पर्यावरण और स्थानीय लोगों की जिंदगी दोनों के लिए जरूरी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की वजह से वन्यजीवों के आवास प्रभावित होंगे, नदियों और झरनों का पानी बदल सकता है और पारंपरिक जीवनशैली पर भी असर पड़ेगा।

पर्यावरण और आदिवासी क्षेत्र बचाने की मुहिम

इस प्रोजेक्ट के विरोध में स्थानीय लोग और गुप्त काशी ट्रस्ट लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रकृति बचेगी तो भविष्य बचेगा।

स्थानीय निवासी और समाजसेवी समूह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ स्वच्छ जंगल और पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा।

सोनभद्र के लोगों से सहयोग की अपील

गुप्त काशी ट्रस्ट और अन्य स्थानीय संगठन लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस मुहिम में सहयोग दें। उनका कहना है कि सिर्फ कोर्ट में केस लड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज की जागरूकता और समर्थन से ही इस प्रोजेक्ट के नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है ।स्थानीय लोग भी इस प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली तो मिल सकती है, लेकिन अगर इसके लिए जंगल, जानवर और आदिवासी जीवन नष्ट हो गया तो इसका लाभ किसी काम का नहीं रहेगा।

भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी

विशेषज्ञ और समाजसेवी दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परियोजना के लिए संतुलित और जिम्मेदार योजना बनाई जानी चाहिए। सिर्फ आर्थिक लाभ या बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना सही नहीं है ।अगर हम आज सोनभद्र के जंगल, आदिवासी और वन्यजीवों को बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। अगर हम इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित होने दें तो न सिर्फ यह इलाका, बल्कि पूरे प्रदेश का पर्यावरण संकट में पड़ जाएगा।

अब अदालत का निर्णय 13 अप्रैल पर

अगली सुनवाई 13 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट में होगी। ट्रस्ट और स्थानीय संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत इस मामले में पर्यावरण और समाज के हित को प्राथमिकता देगी।

इस सुनवाई से पहले ट्रस्ट ने सभी हितधारकों से सुझाव और समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि "सोनभद्र को बचाना सिर्फ आदिवासियों का सवाल नहीं है, यह पूरे समाज का सवाल है। अगर जंगल और नदियां सुरक्षित रहेंगी, तो जीवन सुरक्षित रहेगा।

सोनभद्र का यह पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट न सिर्फ आर्थिक और ऊर्जा के मामले में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण, वन्य जीवन और आदिवासी जीवन के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है।

स्थानीय लोग, ट्रस्ट और समाजसेवी संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

कड़ी मेहनत और आंसुओं की जीत

यूपी पीसीएस 2024 की टॉपर्स की यात्रा

@ आनंद मीणा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) 2024 का फाइनल रिजल्ट रविवार रात साढ़े 12 बजे जारी हुआ। इस साल की परीक्षा ने सिर्फ टॉपर की सूची ही नहीं बनाई, बल्कि कई ऐसे संघर्ष और प्रेरक किस्से सामने लाए जो हर युवा के लिए मिसाल बन सकते हैं ।टॉप करने का सम्मान इस बार दिल्ली की नेहा पंचाल को मिला। उनके बाद रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी दूसरे स्थान पर और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस बार के टॉप 10 में कुल 6 लड़कियां हैं, जो यह दिखाता है कि महिलाओं ने सिविल सेवा की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है।

प्रयागराज में भावनाओं का तूफ़ान

प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वाले आनंद राज सिंह की कहानी खास है। आनंद जब यह खबर सुनते हैं कि वे परीक्षा पास हो गए हैं और 22वीं रैंक हासिल की है, तो सीधे सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर पहुंच गए। मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और फूट-फूटकर रोने लगे। कई मिनट तक उनकी आंखों में खुशी और राहत के आँसू बहते रहे। आनंद सोनभद्र के रहने वाले हैं और अब वे नायब तहसीलदार बनेंगे ।आनंद की यह प्रतिक्रिया बताती है कि यह सफर कितनी मेहनत, संघर्ष और रातों की नींदों का परिणाम है। हर युवा अभ्यर्थी के लिए यही पल सबसे भावनात्मक होता है जब सालों की तैयारी, किताबों और सपनों की मेहनत का फल सामने आता है।

मां बनने के बाद भी बनीं SDM

कानपुर की श्वेता वर्मा इस परीक्षा की दूसरी प्रेरक कहानी हैं। केवल चार महीने पहले ही उन्होंने मां बनने की खुशी महसूस की और अब वह एसडीएम बन गई हैं। उनकी रैंक 21वीं रही। श्वेता का सफर बताता है कि जिम्मेदारियों और परिवार के बीच संतुलन बनाना संभव है, बशर्ते जुनून और मेहनत हो।

आम परिवार से निकलती चमक

कौशांबी के सुनील मौर्य की कहानी और भी दिल को छू लेने वाली है। उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं, और सुनील अब कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (CTO) बन गए हैं। उनकी रैंक 82वीं रही। यह दिखाता है कि यदि इरादा मजबूत हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी उच्चतम स्तर पर सफलता हासिल की जा सकती है ।सेकेंड टॉपर अनन्या त्रिवेदी 25 साल की हैं। उनके पिता सुशील त्रिवेदी परचून की दुकान चलाते हैं और मां रेखा रानी सरकारी टीचर हैं। अनन्या ने पहले प्रयास में ही परीक्षा पास की। उनके मामा राजेश पांडेय कानपुर देहात में एडिशनल एसपी हैं। यह परिवारिक समर्थन और मार्गदर्शन उनकी सफलता की कहानी में अहम भूमिका निभाता है।

महिला अभ्यर्थियों की बढ़ती हिस्सेदारी

इस साल यूपी पीसीएस में कुल 932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें 319 महिलाएं शामिल हैं। कुल चयनितों में 37 बने डिप्टी कलेक्टर (SDM), 17 बने पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और 196 बने असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स)। पिछले साल की तुलना करें तो, पीसीएस-2023 में टॉप 10 में सिर्फ 2 लड़कियां थीं। यह साफ दिखाता है कि सिविल सेवा में महिलाओं का दबदबा लगातार बढ़ रहा है ।947 पदों के लिए कुल 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इनमें से 2698 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि 21 अनुपस्थित रहे। इसके अलावा, 14 पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। यह दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया कितनी कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 30 मार्च 2026 , विक्रम संवत 2080

सच्चाई या राजनीति का शोर?

वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार पूरी दुनिया में लोकप्रियता का एक कीर्तिमान बना रही है । भारत के विपक्षी नेता भी नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता से अपने को परास्त अनुभव कर रहे हैं। उनके सारे दांव पेच असफल होते गए हैं अभी-अभी नरेंद्र मोदी पर अप स्टेट फाइल्स के नाम से हाइड्रोजन बम फेंका गया था लेकिन वह बम भी एक पटाखे से अधिक नहीं निकला। अब कुछ वेश्याओं से संबंध के नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इस संबंध में स्पष्ट हूं कि ऐसी घटनाओं में कुछ सच्चाई भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि यह मामला उन वेश्याओं और नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों का है लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी इस बात को महत्व नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्रह्मचारी रहना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य है। यदि कोई कहता भी है तो वह गलत हो सकता है। मैंने अपने स्वयं का अनुभव करते हुए न कभी गांधी पर आरोप लगाया न नेहरु पर लगाया ना इंदिरा पर लगाया और न कभी और किसी के बारे में चर्चा की क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं कि ब्रह्मचर्य लगभग असंभव है। इसलिए यदि इस प्रकार के आरोप में कोई सच्चाई भी हो तो वह प्रभावहीन है क्योंकि इस आरोप की राजनीति में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं दिखती है ना कभी नेहरु की दिखाई ना इंदिरा की और ना किसी और की इसलिए इन वैश्याओ के संबंध के वार भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हो चुके है और भारत में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है यदि कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में वेश्याओं से संपर्क रखता है तो यह कोई चर्चा की बात नहीं है!

ज्ञानेंद्र आर्य

भारत की नई आपूर्ति रणनीति

@ **अनुराग पाठक**

ईरान और इजरायल/मध्य पूर्व में बढ़ती तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत को गैस की आपूर्ति को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ी है। देश में रसोई गैस की कमी के संभावित संकट को देखते हुए भारतीय सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब नए स्रोतों से LPG खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इस सिलसिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल जैसी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोनांगोल के साथ रसोई गैस खरीदने पर बातचीत कर रही हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बातचीत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यदि यह डील फाइनल होती है तो भारत के लिए यह पहला मौका होगा जब अंगोला से सीधे LPG सप्लाई होगी। वर्तमान में भारत की लगभग 92 प्रतिशत LPG खाड़ी देशों से आयात होती है। इस निर्भरता को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। अंगोला से गैस मिलने पर जहाज सीधे अटलांटिक और अरब सागर मार्ग से भारत आएंगे, और उन्हें जोखिम भरे हॉरमूज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।

भारत और अंगोला के बीच पहले से ही तेल और गैस का व्यापार होता रहा है। दोनों देशों के बीच भरोसा और सप्लाई सिस्टम पहले से मौजूद है, जिससे नई डील को अमली जामा पहनाना अपेक्षाकृत आसान होगा। अंगोला में LPG उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोपेन और ब्यूटेन की पर्याप्त उपलब्धता है, जिससे भारत सीधे गैस प्राप्त कर सकता है।सप्लाई की गति और सुविधा भी अंगोला को विकल्प बनाती है। समुद्री मार्ग से गैस भारत तक 12 से 18 दिन में पहुंच सकती है। इसके अलावा, अंगोला में ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, जिससे सरकारी स्तर पर समझौता करना सरल और पारदर्शी हो सकता है।विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका से गैस सप्लाई अमेरिका की तुलना में 10 से 15 दिन जल्दी भारत पहुंच सकती है। ऐसे में यदि यह समझौता फाइनल होता है, तो अंगोला पहली बार भारत को रसोई गैस सप्लाई करेगा। भारतीय कंपनियां LPG के लिए करीब एक साल और LNG के लिए कम से कम 10 साल के समझौते पर विचार कर रही हैं।

अंगोला के पास लगभग 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है। यह देश पहले से ही भारत को कच्चा तेल और LNG सप्लाई करता रहा है। वित्त वर्ष 2025 में अंगोला भारत का पांचवां सबसे बड़ा LNG सप्लायर था। ऐसे में अंगोला से LPG खरीदना न केवल आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, बल्कि लंबी अवधि में भारत की गैस सुरक्षा में भी योगदान देगा।भारत केवल अंगोला पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी LPG खरीदने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और आपूर्ति में विविधता लाना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए यह रणनीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। गैस संकट का असर न केवल घरेलू रसोई गैस पर होगा, बल्कि उर्वरक और स्टील सेक्टर जैसे बड़े उद्योगों पर भी पड़ सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत को महंगे दामों पर गैस खरीदनी पड़ सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि देश में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में दो बड़े जहाज करीब 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत की ओर रवाना हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि लगातार निगरानी और आपूर्ति विकल्पों का विस्तार भारत के ऊर्जा संकट से निपटने की योजना का हिस्सा है। साथ ही, मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि घरेलू उपयोगकर्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतों में अनावश्यक उछाल न आए। इन कदमों का उद्देश्य न केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा को भी बनाए रखना है।

अंगोला और अन्य देशों से LPG खरीदना भारत के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह कदम देश की खाड़ी देशों पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह समझौता फाइनल होता है, तो भारत के लिए यह आपूर्ति का एक भरोसेमंद और तेज़ मार्ग साबित होगा। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी लंबे अवधि के करार भारत की गैस सुरक्षा को मजबूत करेंगे। इससे घरेलू रसोई गैस, उद्योग और उर्वरक उत्पादन पर दबाव कम होगा।

जुबानी तीर

“ देश में किसी भी प्रकार के ईंधन या रसोई गैस (LPG) की कमी नहीं होने दी जाएगी और सरकार इस मामले पर पूरी तरह तैयार है। LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बनी रहेगी और हर परिवार को गैस मिलेगी। भारत कई देशों से आपूर्ति के विकल्प तलाश रहा है ताकि घरेलू स्तर पर संकट का सामना न करना पड़े।

अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री)

“ सरकार के आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद प्राकृतिक गैस और LPG पर पूरी तरह निर्भरता कम नहीं हुई है और हाल की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने यह निर्भरता उजागर कर दी है। जनता को इस मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए ताकि विश्वास बना रहे।

जयराम रमेश (कांग्रेस नेता)

“ भारत को न केवल स्रोतों को विविध करने की जरूरत है, बल्कि स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति दुर्घटनाओं से निपटने के लिए भविष्य-उन्मुख रणनीति अपनानी चाहिए। केवल अंतरराष्ट्रीय खरीद पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय घरेलू उत्पादन एवं भंडारण क्षमता को मजबूत किया जाए, ताकि संकट की स्थिति में भारत खुद-कुशल बन सके।

डेरेक ओ'ब्रायन (टीएमसी सांसद)

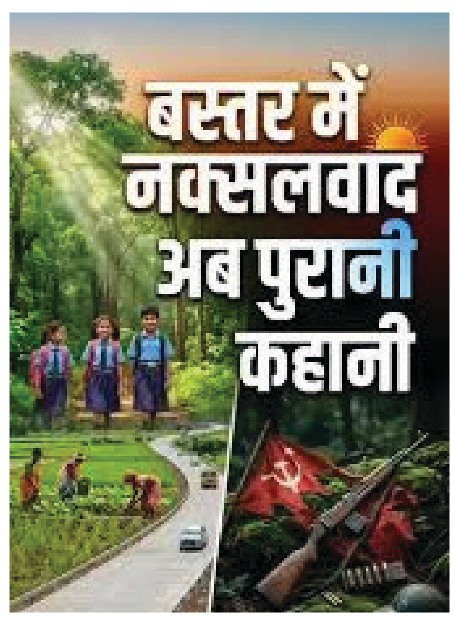

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

सूरज की झुलसा से बचाव

आयुर्वेदिक नुस्खे और प्राकृतिक उपाय

गर्मी के मौसम में सूरज की तेज़ किरणें न केवल हमारी त्वचा को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती हैं। सूरज की झुलसा या सनबर्न एक ऐसी समस्या है जो गर्मियों में आम हो जाती है। यह त्वचा की लालिमा, जलन, खुजली और कभी-कभी फफोले तक पैदा कर सकती है। आयुर्वेद में इस समस्या को "सूर्यकान्ति दोष" से जोड़ा गया है, जो पित्त दोष के असंतुलन के कारण होती है। आयुर्वेद प्राकृतिक उपायों और संतुलित जीवनशैली पर जोर देता है, जो शरीर को ठंडक और सुरक्षा प्रदान करती है।

इस लेख में हम सूरज की झुलसा से बचाव और उपचार के लिए सटीक आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू नुस्खे और जीवनशैली सुझाव साझा करेंगे।

सूरज की झुलसा के लक्षण

सूरज की झुलसा का अनुभव आमतौर पर सीधे धूप में लंबे समय तक रहने के बाद होता है। इसके सामान्य लक्षण हैं:

त्वचा पर लालिमा और सूजन
तेज जलन और खुजली
त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ना
गंभीर मामलों में फफोले या छाले

कभी-कभी सिरदर्द, चक्कर या हल्की बुखार

यदि इन लक्षणों में तेज दर्द, बुखार या पानी से भरे छाले हों, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक है।

आयुर्वेद के अनुसार कारण

आयुर्वेद में सूरज की झुलसा पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ी मानी जाती है। पित्त दोष में गर्मी और उग्रता होती है, जो शरीर की त्वचा पर सीधे असर डालती है। अत्यधिक धूप में रहना, बिना सुरक्षा के बाहर निकलना और पर्याप्त पानी न पीना, यह सभी कारण पित्त को बढ़ाते हैं और त्वचा को जलन का कारण बनते हैं।

आयुर्वेदिक उपाय: त्वचा को ठंडक और सुरक्षा देना

1. एलोवेरा

एलोवेरा का जेल त्वचा को तुरंत ठंडक और आराम प्रदान करता है।

प्रतिदिन ताजे एलोवेरा पत्ते का जेल निकालकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

यह जलन और सूजन को कम करता है और त्वचा की नमी बनाए रखता है।

यदि पत्ते उपलब्ध न हों, तो शुद्ध एलोवेरा जेल का प्रयोग करें।

2. ठंडी दूध और गुलाब जल का मिश्रण

आधा कप ठंडे दूध में 1-2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं।

इसे सनबर्न वाली त्वचा पर 15-20 मिनट तक लगाएं।

दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की सूजन कम करता है और गुलाब जल ठंडक देता है।

3. खीर या हल्दी वाला दूध

आयुर्वेद में हल्दी को त्वचा के लिए उत्कृष्ट माना गया है।

1 कप दूध में चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर के अंदर से पित्त नियंत्रित होता है और त्वचा में लालिमा कम होती है।

4. खस्ता पत्ता और नीम का लेप

नीम और खस्ता पत्ते की पेस्ट बनाकर प्रभावित त्वचा पर लगाएं।

यह बैक्टीरियल संक्रमण से बचाता है और त्वचा को ठंडक प्रदान करता है।

20-30 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें।

5. दही और खीरे का पेस्ट

दही में कच्चा खीरा पीसकर मिश्रण बनाएं।

इसे 15-20 मिनट प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

दही त्वचा को ठंडक देता है और खीरा जलन को कम करता है।

6. संतरे और नींबू का रस

नींबू और संतरे का रस विटामिन C से भरपूर होता है।

1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच संतरे का रस मिलाकर प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथ से लगाएं।

यह त्वचा को ठंडक देने के साथ पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है।

आहार और जीवनशैली से बचाव

सिर्फ बाहरी उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं। आयुर्वेद में आहार और जीवनशैली का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

पानी का सेवन बढ़ाएं

गर्मियों में अधिक पानी, नारियल पानी और तरल पदार्थ पिएं।

यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और त्वचा की सूजन कम करता है।

ठंडे और पित्त शांत करने वाले आहार

दही, खीरा, तरबूज, पपीता, और संतरा पित्त को नियंत्रित करते हैं।

तीखे मसाले और तैलीय भोजन कम करें।

धूप से बचाव

सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद ही धूप में बाहर निकलें।

हमेशा हैंडहैट, छाता या हल्के रंग के कपड़े पहनें।

नियमित स्नान

गुनगुने पानी से रोजाना स्नान करें।

त्वचा को ठंडक देने के लिए दही या एलोवेरा का लेप स्नान के बाद लगाएं।

घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक तेल

नारियल तेल

नारियल तेल में ठंडक और नमी दोनों होती है।

धूप में निकलने से पहले हल्का तेल लगाना त्वचा को सुरक्षा देता है।

अलसी का तेल

अलसी का तेल पित्त दोष को शांत करता है और त्वचा की सूजन को कम करता है।

प्रभावित हिस्से पर हल्का मालिश करने से राहत मिलती है।

जौ का आटा

जौ के आटे को पानी या गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं।

इसे सनबर्न वाली त्वचा पर लगाएं।

10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

मानसिक स्वास्थ्य और सूर्य के प्रति सजगता

आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। मानसिक संतुलन और सजगता भी जरूरी है।

सूरज के प्रति सावधानी और समय का ध्यान रखें।

त्वचा पर जलन या झुलसा महसूस होने पर तुरंत ठंडक और आराम दें।

तनाव और नींद की कमी से पित्त दोष बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद और योग/ध्यान करें।

गर्मी के मौसम में सूरज की तेज किरणों से सुरक्षा पाना न केवल त्वचा की सुंदरता के लिए जरूरी है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनिवार्य है। आयुर्वेदिक उपाय जैसे एलोवेरा, ठंडे दूध, दही और नीम-पत्ते का लेप, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी शरीर और त्वचा दोनों को ठंडक प्रदान करते हैं।

सूरज की झुलसा को गंभीर रूप में लेने से बचाव और इलाज आसान हो जाता है। घरेलू उपायों और प्राकृतिक नुस्खों के साथ जीवनशैली में बदलाव, धूप से बचाव और पित्त दोष को नियंत्रित करने वाले आहार अपनाना आयुर्वेद की सर्वोत्तम सिफारिश है।

इन उपायों से न केवल झुलसा से बचाव होगा, बल्कि त्वचा स्वस्थ, ठंडी और चमकदार भी बनी रहेगी। गर्मी में संतुलित जीवनशैली और प्राकृतिक उपचार अपनाना ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है।

पाठकों के सवाल

क्या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है और आप उसका समाधान आयुर्वेद के माध्यम से जानना चाहते हैं? अब आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर अनुभवी आयुर्वेदाचार्य द्वारा दिया जाएगा और उन्हें इस पेज पर प्रकाशित किया जाएगा।

अपने सवाल हमें ईमेल करें
hi@bharatshri.com

कृपया अपने सवाल के साथ अपनी उम्र, शहर और समस्या का संक्षिप्त विवरण अवश्य लिखें, ताकि विशेषज्ञ सही सलाह दे सकें।

जब भक्ति बनी जीवन का सार

विट्ठलनाथ जी का अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी परम रससिद्ध महात्मा थे। उन्होंने पुष्टिमार्ग की मर्यादा के अनुसार श्रीकृष्ण और उनकी प्राणप्रियतमा राधारानी की रसमयी लीला का चिंतन अमित विद्वत्ता से किया। कर्म और ज्ञान दोनों को भक्ति की कालिन्दी में रसमग्न करके उन्होंने लोकजीवन का सरस आत्मोत्थान किया। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुण्य के पुञ्जीभूत स्वरूप थे। भागवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए धरती पर उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने समस्त प्राणीमात्र को श्रीकृष्ण की भक्ति का अधिकारी घोषित किया।

निस्संदेह उनके भजन के प्रताप से कलियुग कृष्णभक्ति में सरस होकर वृन्दावन की शुद्ध सच्चिदानन्दमयी तथा अलौकिक दिव्य वात्सल्य-लीला और कमनीय कुंज की केलि से द्वापर में रूपांतरित हो गया। उन्होंने भगवान कृष्ण की परिचर्या और सेवा का राग, भोग, शय्या, भूषण, वसन आदि से युक्त विधान स्थिर किया।

भक्तों की श्रद्धा और वाणी

मध्यकालीन भक्ति-साहित्य ने नन्ददास, छीतस्वामी आदि के वाणी-माध्यम से उनके चरणों में अमित विश्वास प्रकट किया है। छीतस्वामी की उक्ति है कि हम तो वल्लभनन्दन विठ्ठलनाथ की उपासना और भक्ति करते हैं। वे साक्षात् मुक्तिस्वरूप हैं। उनको छोड़कर किसी अन्य का ध्यान नहीं किया जा सकता। उनका आश्रय ग्रहण करना सर्वथा वैदिक है, वेदसम्मत है।

छीतस्वामी ने विठ्ठलनाथ में गुरुभावना और भगवद्भक्ति की अभिन्नता की अनुभूति की। गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने भगवद्भक्ति के अवलम्बन से युगांतर उपस्थित किया। उन्होंने म्लेच्छ से आक्रांत देश में वैदिक मर्यादा की पवित्रता का संरक्षण किया।

नन्ददास की उक्ति है :

"श्रीवल्लभसुत के चरण भजो। नन्द सुकुमार भजन सुखदायक

पतितन पावन करन भजो। पुष्टि मर्याद, भजन-सुखसीमा, निज जन पोषन करन भजो।

'नन्ददास' प्रभु प्रकट भये दोउ श्री विठ्ठलेश गिरिधरन भजो।"

प्रेमलक्षणा भक्ति और कृपा

विठ्ठलनाथ ने प्रेमलक्षणाभक्ति सिद्ध की। उन्होंने असंख्य प्राणियों को भगवान के चरणारविंद में प्रणत कर ब्रह्मसम्बन्ध कराया। उनकी कृपा से साहित्य, संगीत और कला ने भक्ति के चरण पर आत्मसमर्पण कर दिया। गोस्वामी विठ्ठलनाथ भक्ति-सूत्रधार महाप्रभु वल्लभाचार्य के आत्मज थे। उनके जन्म से परम पवित्र तैलंग कुल ही नहीं, समस्त भरतखण्ड धन्य हो गया।

जन्म और बाल लीला

गोस्वामी विठ्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र थे। उनका जन्म काशी के सन्निकट चरणाट-चुनार में सम्वत् 1572 वि में पौष कृष्ण नवमी को हुआ था। उस समय महाप्रभु चरणाट में ही निवास कर रहे थे। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। व्रज में महाकवि सूरदास आदि ने वधाई के पद गाए। परम भागवत ज्योति का धरती पर असंख्य जीवों को तारने के लिए अवतरण हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम मुदित थे। अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर उन्होंने प्रचुर दान दिया।

वर्णन मिलता है कि जन्म के एक मास के बाद विधिपूर्वक गंगा-पूजन हुआ। सौभाग्यवती लक्ष्मी देवी अपनी गोद में पुत्र को लेकर गंगा-पूजन कर रही थी कि इतने में गंगाजल में बाढ़ आ गई। भागीरथी ने नवजात का चरण स्पर्श किया। साक्षात् प्रकट होकर लक्ष्मी के भाग्य की सराहना की कि तुम्हारे पति साक्षात् पुरुषोत्तम हैं और पुत्र भी पुरुषोत्तम रूप में प्रकट हुआ।

कुम्भनदास का पद है :

"प्रकटे श्री विट्ठलेश लाल गोपाल ।

कलियुग जीव उधारन कारन सत जनन प्रतिपाल ।

द्विज कुल मण्डन तिलक तैलग-वल्लभ कुल अतिरसाल ।

'कुम्भनदास' प्रभु गोवरधनघर नित उठि नेह करत व्रजवाल ।।"

संस्कार और शिक्षा

सम्वत् 1580 वि में अडैल में उनका यज्ञोपवीत-संस्कार सम्पन्न हुआ। उनकी शिक्षा-दीक्षा अडैल में ही हुई। पिता की तरह उन्होंने भी गृहस्थाश्रम ही स्वीकार किया। दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी और दूसरी का नाम पद्मावती था।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने अपने जीवन का अधिकांश गोकुल और गोवर्धन में बिताया। व्रज के प्रति वे स्वभाव से ही आकृष्ट थे। धीरे-धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। सम्वत् 1587 वि में महाप्रभु वल्लभाचार्य के नित्य गोलोक-प्रवेश के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी पुष्टिमार्ग के आचार्य हुए। पर थोड़े समय के बाद उनका गोलोक-गमन हुआ। विठ्ठलनाथ जी सपरिवार अडैल से व्रज आ गए थे।

आचार्य पद की प्राप्ति और विरह

उत्तरा-विकार का प्रश्न छिड़ने पर गोपीनाथ जी की पत्नी ने अपने पुत्र पुरुषोत्तम जी का पक्ष लिया। कृष्णदास जी भी पुरुषोत्तम जी की ही ओर थे। श्रीविठ्ठलनाथ जी ने आचार्यपद की अधिकार-याचना की पर मान्यता नहीं दी गई। वे श्रीनाथ जी में दृढ़ अनुरक्त और आसक्त थे। कृष्णदास ने उनका ड्योढ़ी-दर्शन भी बंद कर दिया।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ श्रीनाथ जी के विरह-दुख से इतने सतप्त हो गए कि उनका समय कटना कठिन हो गया। वे परासोली चले गए। वहां से नित्य नियमपूर्वक श्रीनाथ जी के मन्दिर के झरोखे की ओर देखा करते थे और उनकी पताका को श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार कर लिया करते थे।

गोविन्ददास का इस घटना के संबंध में पद है जिससे गोस्वामी विठ्ठलनाथ की वास्तविक मनोदशा का पता चलता है :

"चितवत रहत सदा गोकुल तन । बार-बार खिरकी हह्व झौकत अति आतुर पुलकित मन ।

सुख चाहत है भरत कमल दल लोचन । ताही समं मिलेगी 'गोविन्द' प्रभु कुमर विरह-दुख मोचन ।"

विज्ञप्ति रचना और कृपालु हृदय

परासोली-निवास काल में उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग-दुख में 'विज्ञप्ति' की रचना की। उनके पुत्र गिरिधर ने मथुरा के शासक से शिकायत कर कृष्णदास को कैद करवा दिया। गोस्वामी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अन्न-जल त्याग दिए। उनका उदार और कृपालु हृदय द्रवित हो उठा। कृष्णदास के मुक्त होने पर उन्होंने भोजन किया। कृष्णदास गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के इस सहानुभूति-पूर्ण आचरण से बहुत प्रभावित हुए।

लीला समाप्ति और विरह

इस धरती पर बहुत दिनों तक भक्ति का प्रचार कर उन्होंने जीवन-लीला-संवरण किया। सम्वत् 1642 वि में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को गोवर्धन की एक कन्दरा में प्रवेश कर उन्होंने शरीर त्याग किया। उनके लीला-प्रवेश के समय अष्टछाप के संत चतुर्भुजदास उपस्थित थे। वातावरण करुणरस से आप्लावित था। उन्होंने अमित करुण स्वर में गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट कीः

"श्री विठ्ठलनाथ से प्रभु भये न ह्वे है। पाछे सुने न देखे आगे, वह सग फिरि न वर्न है।

को फिरि नन्दराय को वैभव व्रजवासिनि विलसै है। श्री वल्लभ सुत दर्शन कारन अव सव कोउ पछिते है। 'चतुर्भुजदास' आस इतनी जो सुमिरन जनमु सिरै है।"

उनका समस्त जीवन भगवान कृष्ण की सौन्दर्य-माधुर्य-लीला के दर्शन-चिंतन का चिन्मय प्रतीक है। उनकी गोलोकयात्रा के बाद उनकी गद्दी उनके सात पुत्रों में विभाजित हो गई। लोक-जीवन में लोकोत्तरता और चिन्मयता अथवा अलौकिकता का समावेश पुष्टिमार्ग की विशेषता है और इस मर्म के अप्रतिम मर्मज्ञ गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी स्वीकार किए जाते हैं।

रचनाएं

विद्वन्मण्डन, निबन्धप्रकाश टीका, सुवोधिनी की टिप्पणी, भक्तिहेतु शृंगाररसमण्डन, भक्ति हंस, विज्ञप्ति आदि विठ्ठलनाथ जी की रचनाएं हैं।

केरल में भाजपा की दस्तक

बढ़ती सक्रियता, लेकिन सत्ता अभी दूर

वोट शेयर में उछाल, संगठन में मजबूती और नए सामाजिक समीकरण-फिर भी सीटों में क्यों नहीं बदल रही भाजपा की मेहनत?

केरल में भाजपा अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रही है। पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और तीन लिस्ट जारी कर चुकी है। राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नेमोम से लड़ रहे हैं, जहां पार्टी का पुराना आधार है। साथ ही, कई ईसाई उम्मीदवारों को टिकट देकर पार्टी ने अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। हाल के लोकल बॉडी चुनावों में भाजपा ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में 50 सीटें जीतकर इतिहास रचा। यह पहली बार था जब 45 साल पुरानी लेफ्ट की पकड़ टूटी। 2024 लोकसभा चुनाव में सुरेश गोपी ने त्रिशूर से जीत हासिल कर केरल में भाजपा का पहला सांसद बना दिया। पार्टी अब विकास, केंद्र की योजनाओं और स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी पर फोकस कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे अभी भी हिंदुत्व की राजनीति बता रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव में पहुंच रहे हैं और छोटे-छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, जहां भाजपा तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी की मेहनत बढ़ी है, लेकिन क्या यह वोट में बदल जाएगी, यह देखना बाकी है। कुल मिलाकर, भाजपा केरल में अब चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि जोर-शोर से लड़ाई लड़ रही है।

वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन सीटों की दूरी अब भी भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है।
केरल की राजनीति में जगह बन रही है, लेकिन जीत अभी संघर्ष मांगती है।
संगठन मजबूत, रणनीति सक्रिय–फिर भी सत्ता की राह क्यों कठिन है?
तीसरा विकल्प बनना आसान था, निर्णायक ताकत बनना असली परीक्षा है।
केरल में भाजपा का सफर लंबा है–हर जीत एक कदम, हर हार एक सबक।

भाजपा का केरल में पूरा इतिहास

भाजपा का केरल में सफर लंबा और धीमा रहा है। 1980 के दशक में पार्टी ने यहां काम शुरू किया, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 2-3 प्रतिशत के आसपास था। 2006 के चुनाव में वोट 4.75 प्रतिशत पहुंचा, 2011 में 6 प्रतिशत हुआ। फिर 2016 में बड़ा ब्रेकथ्रू आया। ओ राजगोपाल ने नेमोम सीट से जीत हासिल की और केरल का पहला भाजपा विधायक बने। वोट शेयर 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में नेमोम हाथ से निकल गई और पार्टी 11.3 प्रतिशत वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी। लोकसभा में भी लंबे समय तक शून्य रहा, लेकिन 2024 में त्रिशूर से सुरेश गोपी की जीत ने इतिहास बनाया। वोट शेयर 16.8 प्रतिशत हो गया। लोकल बॉडी चुनाव 2025 में तिरुवनंतपुरम में बड़ी सफलता मिली। पार्टी ने संगठन मजबूत किया, युवाओं को जोड़ा और गठबंधन बनाए। लेकिन हर बार वोट बढ़ने के बावजूद सीटें कम मिलीं। इतिहास बताता है कि भाजपा ने कभी हार नहीं मानी। छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ती रही। आज केरल में भाजपा का वजूद पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन अभी भी मुख्यधारा की राजनीति से थोड़ा दूर है। यह सफर दिखाता है कि धैर्य और मेहनत से कुछ हासिल होता है।

क्या केरल में भाजपा का खेल बदलेगा

आगे चलकर केरल में भाजपा का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। पार्टी संगठन मजबूत कर रही है, युवाओं और महिलाओं को साथ ले रही है। अगर स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार और बाढ़ जैसी समस्याओं पर काम जारी रखा तो धीरे-धीरे वोट बढ़ सकता है। हाल के ब्रेकथ्रू से लगता है कि अभेद्य दीवार पर दरारें पड़ रही हैं। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। भाजपा को सेकुलर छवि बनाने और सभी समुदायों का भरोसा जीतने की जरूरत है। अगर पार्टी विकास की राजनीति पर फोकस करे तो भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। केरल के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन तेजी से नहीं। धीरे-धीरे भाजपा की पैठ बढ़ रही है। 2026 के बाद अगर कुछ सीटें मिलीं तो अगले चुनाव में और बढ़ोतरी हो सकती है। यह सफर सिखाता है कि राजनीति में धैर्य जरूरी है। केरल की सियासत में भाजपा अब तीसरा विकल्प बन चुकी है। क्या यह विकल्प मजबूत बनेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है -भाजपा हार मानने वाली नहीं है।

2026 चुनाव में भाजपा कितनी सीटें निकाल सकती है

2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कितनी सीटें निकाल सकती है, यह सवाल सबको परेशान कर रहा है। पार्टी 100 सीटों पर लड़ रही है और नेमोम, कझाक्कूट्टम, अरनमुला जैसे 8-10 सीटों पर मजबूत दावेदार है। हाल के लोकल बॉडी और लोकसभा नतीजों से उम्मीद बढ़ी है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। नेमोम में राजीव चंद्रशेखर की लड़ाई करीबी हो सकती है। त्रिशूर इलाके में भी भाजपा की पकड़ अच्छी है। लेकिन लेफ्ट और यूडीएफ का गठबंधन मजबूत है। अगर वोट शेयर 12-15 प्रतिशत रहा तो भी सीटें कम ही मिलेंगी। एक ओपिनियन पोल में कहा गया है कि भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीत सकता है। पार्टी विकास और केंद्र की मदद पर वोट मांग रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा अभी भी मार्जिनल फोर्स है। चुनाव 9 अप्रैल को है और नतीजे 4 मई को आएंगे। अगर भाजपा नेमोम और एक-दो और सीटें जीत गई तो यह बड़ा ब्रेकथ्रू होगा। लेकिन 71 सीटों के बहुमत की बात अभी दूर है। कुल मिलाकर, भाजपा की कोशिश अच्छी है, लेकिन नतीजे सीमित ही रहने की उम्मीद है।

क्यों केरल भाजपा के लिए हमेशा कठिन रहा

केरल भाजपा के लिए हमेशा से अभेद्य क्यों रहा, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यहां की द्विध्रुवीय राजनीति है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच वोट ट्रांसफर होता रहता है, जिससे भाजपा को नुकसान पहुंचता है। राज्य में 55 प्रतिशत हिंदू हैं, लेकिन ईसाई और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। ये समुदाय भाजपा की हिंदुत्व वाली छवि से थोड़ा डरते हैं। केरल की उच्च साक्षरता और सेकुलर सोच ने हमेशा कम्युनल राजनीति को दूर रखा है। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेफ्ट की जड़ें यहां बहुत गहरी हैं। किसान, मजदूर और शिक्षक यूनियन लेफ्ट के साथ हैं। कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतती आई है। भाजपा को यहां बाहरी पार्टी समझा जाता था। गठबंधन राजनीति में छोटी पार्टियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। 2016 और 2021 में वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें नहीं मिलीं क्योंकि विरोधी एकजुट हो गए। केरल की संस्कृति सहिष्णुता पर टिकी है, जहां भाजपा की कुछ नीतियां अलग दिखती हैं। फिर भी, हाल के सालों में पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर काम करके थोड़ी जगह बनाई है। ये कारण बताते हैं कि केरल की जमीन भाजपा के लिए आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं।

दुनिया चल कैसे रही है?

ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतु खुशबू जी का चिंतन

जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है, जब इंसान अचानक रुक जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है,,,काम, रिश्ते, दिनचर्या लेकिन भीतर कहीं एक सवाल उठता है: आखिर यह सब चल कैसे रहा है? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या उसका कोई गहरा कारण है, या मैं बस परिस्थितियों का हिस्सा हूँ?यह सवाल साधारण नहीं है। यही वह क्षण है, जब इंसान भीड़ से अलग होता है। जब वह केवल जीना नहीं, समझना चाहता है। यह समझने की इच्छा ही उसे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि जवाब बाहर मिल जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे वह खोजता है, उसे एहसास होता है कि बाहर केवल संकेत हैं, सच्चाई कहीं और है।

समय जो दिखता है, वही सच नहीं होता

सबसे पहले इंसान समय को कारण मानता है। उसे लगता है कि समय ही सब कुछ बदल रहा है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा—और जो कल था, वह आज नहीं है ।यह सोच आसान है, क्योंकि हम हर दिन बदलाव देखते हैं। लेकिन गहराई में जाएँ, तो सवाल उठता है -क्या समय खुद कुछ करता है?अगर इस दुनिया में कुछ भी न बदले,,न दिन बदले, न शरीर, न विचार तो क्या समय का अनुभव होगा? नहीं ।इसका मतलब साफ है समय कारण नहीं है। वह तो केवल बदलाव का एक पैमाना है। वह बताता है कि कुछ बदला है, लेकिन यह नहीं बताता कि क्यों बदला।

स्वभाव सही लगता है, पर पूरा नहीं

फिर इंसान कहता है कि हर चीज अपने स्वभाव से काम कर रही है। आग जलाती है, पानी ठंडा करता है यह उनका स्वभाव है ।यह बात सही लगती है, लेकिन अधूरी है ।क्योंकि सवाल यह है कि स्वभाव किसका है? अगर कोई वस्तु है, तभी उसका स्वभाव होगा। और अगर वह वस्तु है, तो वह आई कहाँ से?यानी स्वभाव केवल व्यवहार को समझाता है, अस्तित्व को नहीं।

भाग्य-आराम देता है, पर इंसान को रोक देता है

जब इंसान थक जाता है, तो वह कहता है-सब कुछ पहले से तय है ।यह सोच थोड़ी राहत देती है। हमें लगता है कि जो हो रहा है, वही होना था ।लेकिन यह सोच खतरनाक भी है। क्योंकि अगर सब तय है, तो फिर प्रयास का क्या मतलब? अगर हमारी मेहनत का कोई असर नहीं है, तो फिर हम क्यों आगे बढ़ें?यह सोच धीरे-धीरे इंसान को कमजोर बना देती है।

संयोग-जब समझ नहीं आती, तो हम उसे नाम दे देते हैं

कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ बस यूँ ही हो रहा है। कोई कारण नहीं है, सब संयोग है ।लेकिन यह जवाब भी टिकता नहीं ।अगर सब कुछ संयोग होता, तो यह दुनिया इतनी व्यवस्थित क्यों होती? हर चीज एक लय में क्यों चलती?हमारा शरीर इतनी सटीकता से कैसे काम करता? प्रकृति में इतना संतुलन कैसे बना रहता?संयोग से इतनी सुसंगतता संभव नहीं है।

जो दिख रहा है, क्या वही पूरा सच है?

अब इंसान कहता है-जो दिखता है, वही सच है। सब कुछ पदार्थ है ।यह सोच आधुनिक है, वैज्ञानिक है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी कमी है ।अगर सब कुछ पदार्थ है, तो अनुभव करने वाला कौन है? मैं कौन हूँ?हम केवल चीजों को नहीं देखते, हम उन्हें महसूस भी करते हैं। हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, याद रखते हैं ।क्या यह सब केवल पदार्थ से संभव है?

असली मोड़-जब खोज बाहर से भीतर मुड़ती है

अब तक इंसान ने हर जगह खोजा,,समय में, स्वभाव में, भाग्य में, संयोग में, पदार्थ में ।लेकिन कोई भी जवाब उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया ।यहीं से एक नया मोड़ आता है ।अब वह बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है ।वह देखता है कि उसका शरीर बदल रहा है। विचार बदल रहे हैं। भावनाएँ बदल रही हैं ।लेकिन एक चीज है, जो नहीं बदल रही वह है देखने वाला।

जो देख रहा है, वही सबसे बड़ा रहस्य है

आप अपने शरीर को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप शरीर नहीं हैं ।आप अपने विचारों को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप विचार नहीं हैं ।आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप भावनाएँ भी नहीं हैं ।तो फिर आप कौन हैं?यही वह सवाल है, जो इंसान को सच्चाई के सबसे करीब ले जाता है।

सबसे बड़ी भूल-हमने खुद को गलत समझ लिया

हम दुखी इसलिए होते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान गलत बना ली है ।हम अपने आपको शरीर मान लेते हैं-इसलिए शरीर का हर दर्द हमें अपना लगता है ।हम अपने आपको मन मान लेते हैं-इसलिए हर छोटी बात हमें हिला देती है ।यह एक भ्रम है ।जैसे कोई व्यक्ति सपने में डर जाता है, और जागने पर समझता है कि वह सब झूठ था-वैसे ही हम इस जीवन को पूरी सच्चाई मान लेते हैं।

समस्या बाहर नहीं, हमारी समझ में है

हम सोचते हैं कि अगर हमारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, तो हम खुश हो जाएँगे ।लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएँ कभी खत्म नहीं होतीं—वे केवल बदलती रहती हैं ।असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है ।जब हमारी समझ बदलती है, तब वही दुनिया हमें अलग दिखाई देने लगती है।

देखने वाला बनना-जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन

जब इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल देखने वाला है, तब उसका जीवन बदल जाता है ।अब वह हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता ।वह हर चीज से भागता भी नहीं है ।वह बस देखता है ।और यह देखना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।

सुख और दुख दोनों को समझने का तरीका बदल जाता है

पहले इंसान सुख को पकड़ना चाहता था और दुख से भागना चाहता था ।लेकिन अब वह समझ जाता है कि दोनों अस्थायी हैं ।अब सुख आता है, तो वह उसे महसूस करता है, लेकिन उसमें खोता नहीं ।दुख आता है, तो वह उसे देखता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं ।हम सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो चाहो, वह कर सको ।लेकिन असली आज़ादी यह है कि जो हो रहा है, वह आपको भीतर से हिला न सके ।आपके भीतर एक ऐसी जगह हो, जहाँ कोई हलचल न हो ।जहाँ आप हमेशा शांत रह सकें।

जब यह समझ गहरी होती है

जब यह समझ धीरे-धीरे भीतर उतरती है, तब इंसान के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है ।अब वह चीजों को पहले की तरह नहीं देखता ।अब वह हर अनुभव को समझता है ।अब जीवन उसके लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है।

खोज का अंत और असली शुरुआत

एक समय आता है, जब इंसान समझ जाता है कि वह जितना बाहर खोज रहा था, उतना ही वह खुद से दूर जा रहा था ।और जैसे ही वह भीतर मुड़ता है, उसे एहसास होता है कि सच्चाई हमेशा से उसके भीतर थी।

आप वही हैं, जिसे आप खोज रहे थे

हम पूरी ज़िंदगी कुछ पाने की कोशिश करते हैं-खुशी, शांति, संतोष ।लेकिन अंत में आकर समझ में आता है कि यह सब कहीं बाहर नहीं था ।यह सब हमारे भीतर था ।हम वही हैं, जिसे हम पूरी ज़िंदगी खोज रहे थे ।जब यह समझ पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, तब जीवन में एक गहरी शांति आ जाती है ।अब कोई सवाल नहीं बचता ।कोई बेचैनी नहीं बचती ।कोई भागदौड़ नहीं बचती ।बस एक स्थिरता बचती है।

जीवन को देखने का नया तरीका

अब इंसान जीवन को अलग नजर से देखता है ।वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है, वह बदलने वाला है ।लेकिन जो देख रहा है, वह कभी नहीं बदलता ।और यही समझ उसे स्थिर रखती है ।अंत में इंसान यह समझता है कि उसे कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है ।उसे केवल यह समझना है कि वह क्या है ।और जैसे ही यह समझ आती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है ।जीवन को बदलने की जरूरत कभी नहीं थी ।जरूरत केवल उसे सही तरीके से देखने की थी ।और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वैसे ही पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है ।यह पूरी यात्रा हमें एक ही जगह लाती है अपने भीतर ।जहाँ न कोई डर है, न कोई संघर्ष ।जहाँ केवल शांति है ।और जब इंसान वहाँ पहुँच जाता है, तब उसे समझ में आता है कि दुनिया को समझने की कोशिश में वह जहाँ-जहाँ भटका, वह सब जरूरी था ।क्योंकि उसी भटकाव ने उसे उसके अपने सत्य तक पहुँचाया ।और वही सत्य उसकी सबसे बड़ी मुक्ति है। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद् के प्रथमोध्याय में लिखा है -

कालः स्वभावो नियतिर् यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषेति चिन्त्यम् ।
संयोग एषां न त्वात्मभावाद् आत्मा ह्यनीशः सुखदुःखहेतोः ।।२।।

अडानी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रीन एनर्जी तक-तेज रफ्तार विकास या बढ़ता केंद्रीकरण?

पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली और ग्रीन एनर्जी में आक्रामक विस्तार-क्या यह भारत की ग्रोथ का इंजन है या बाजार में असंतुलन की शुरुआत?

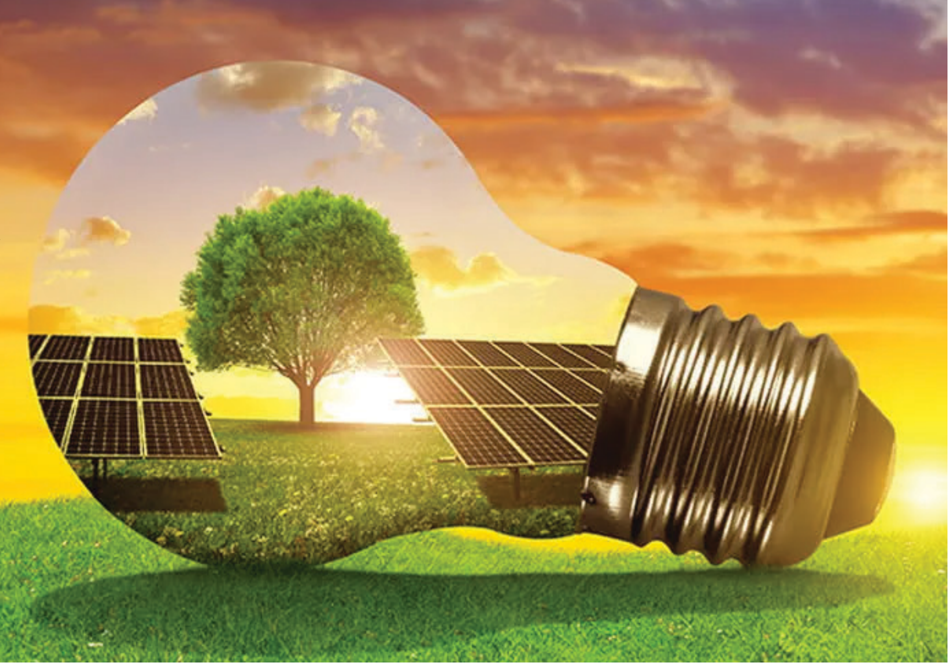

अडानी ग्रुप आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े नामों में से एक है। उनके पास 15 पोर्ट हैं जो देश के व्यापार को आसान बनाते हैं। 2025 में केरल का विजिनजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पहली फेज में पूरी तरह चालू हो गया। यह भारत का पहला बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो जहाजों को आसानी से माल लोड-अनलोड करने में मदद करेगा। इसी साल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली फेज भी शुरू हुई। यह दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक बनेगा। अडानी ग्रुप पहले से ही अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे कई एयरपोर्ट चला रहा है। इन सब कामों से यातायात तेज हुआ है और व्यापार बढ़ रहा है। असल में अडानी का तरीका यह है कि वे पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट को एक साथ जोड़ते हैं। इससे माल की आवाजाही सस्ती और तेज हो जाती है। सरकार की गति शक्ति योजना ने भी इन्हें मदद दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा एक ही ग्रुप के पास होने से दूसरे छोटे खिलाड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिर भी रोजगार बढ़ा है और देश की इकोनॉमी को फायदा पहुंच रहा है। अडानी पोर्ट्स के कारोबार में 2025 में 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। यह दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी मजबूत है। आम आदमी के लिए इसका मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ता सामान। लेकिन लंबे समय में फेयर कंपटीशन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि सबको मौका मिले।

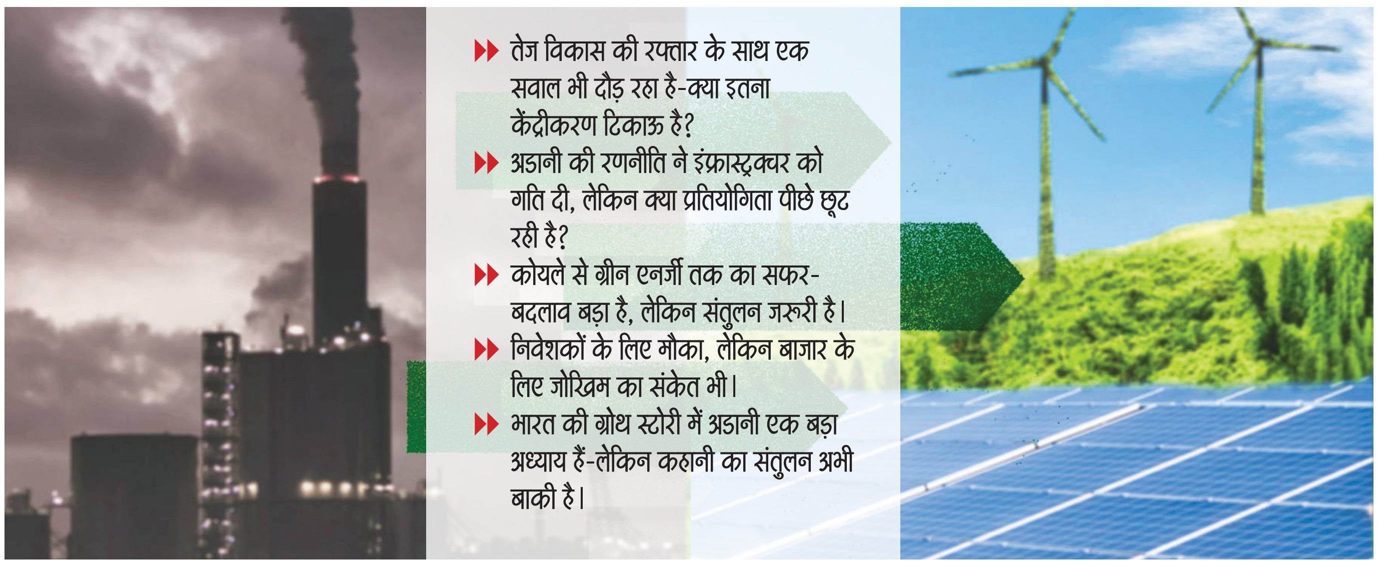

- तेज विकास की रफ्तार के साथ एक सवाल भी दौड़ रहा है-क्या इतना केंद्रीकरण टिकाऊ है?
- अडानी की रणनीति ने इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी, लेकिन क्या प्रतियोगिता पीछे छूट रही है?
- कोयले से ग्रीन एनर्जी तक का सफर-बदलाव बड़ा है, लेकिन संतुलन जरूरी है।
- निवेशकों के लिए मौका, लेकिन बाजार के लिए जोखिम का संकेत भी।
- भारत की ग्रोथ स्टोरी में अडानी एक बड़ा अध्याय है-लेकिन कहानी का संतुलन अभी बाकी है।

कोयला और बिजली से ग्रीन एनर्जी की तरफ बदलाव

अडानी ग्रुप कोयला और थर्मल पावर से शुरू हुआ था लेकिन अब ग्रीन एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी है जो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी है। 2025 तक उनके पास 14.2 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी थी और 2030 तक 50 गीगावाट का टारगेट है। गुजरात का खावड़ा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जहां 30 गीगावाट तक बिजली बनेगी। 2025 में उन्होंने 2.4 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी और अगले साल 5 गीगावाट और जोड़ने वाले हैं। कोयला अभी भी है लेकिन वे थर्मल पावर को भी अपग्रेड कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े प्लांट लगा रहे हैं। अदानी पावर थर्मल में भी विस्तार कर रही है लेकिन रिन्यूएबल मिक्स बढ़ा रही है। मुंबई में उनकी बिजली कंपनी ने रिन्यूएबल शेयर 38 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य में मदद कर रहा है। असली कहानी यह है कि अडानी ने कोयला खदान से पोर्ट तक और फिर पावर तक सब कुछ अपने हाथ में लिया। इससे लागत कम हुई और स्पीड बढ़ी। सरकार की रिन्यूएबल नीतियों ने भी सपोर्ट दिया। लेकिन कुछ विशेषज्ञ चिंता करते हैं कि कोयला पावर अभी भी बढ़ रही है तो पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। फिर भी ग्रीन एनर्जी में उनका निवेश 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। आम लोगों के लिए सस्ती और साफ बिजली का फायदा होगा।

शेयर बाजार में अडानी का कमाल: निवेशकों के लिए क्या मायने

पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप के शेयरों ने उतार-चढ़ाव के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। 2025 में अदानी पावर के शेयर 36 प्रतिशत बढ़े जबकि अदानी पोर्ट्स 21 प्रतिशत और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 23 प्रतिशत ऊपर गए। अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक 5 साल की CAGR 13 प्रतिशत के आसपास रही लेकिन लंबे समय में कई गुना रिटर्न दिए। 2014 से 2025 तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैप कई गुना बढ़ा जबकि टाटा और रिलायंस जैसे दूसरे ग्रुप्स की तुलना में यह ग्रोथ सबसे तेज रही। 2023 के हिंदनबर्ग विवाद के बाद शेयर गिरे लेकिन 2025 में रिकवरी हुई। अब ग्रुप का कुल EBITDA 86 हजार करोड़ से ज्यादा है। निवेशक इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में सरकार का फोकस है। लेकिन जोखिम भी है। एक ही ग्रुप पर इतना निर्भर होना बाजार को प्रभावित कर सकता है। फिर भी जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उन्हें फायदा हुआ है। आम आदमी के लिए यह दिखाता है कि अच्छी प्लानिंग और एक्जीक्यूशन से बिजनेस बढ़ सकता है। शेयर बाजार में अडानी का राइज भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है लेकिन विविधता बनाए रखना जरूरी है ताकि जोखिम कम हो।

पावर का सेंट्रलाइजेशन-पहले भी हुआ या नया ट्रेंड?

क्या कभी इतना बड़ा पावर सेंट्रलाइजेशन हुआ है? भारत में पहले भी बड़े ग्रुप्स ने कई सेक्टर संभाले हैं। टाटा ग्रुप 100 साल से स्टील, ऑटो और पावर में मजबूत है। रिलायंस ने टेलीकॉम में जियो के जरिए पूरा बाजार बदल दिया। लेकिन अडानी ग्रुप की स्पीड अलग है। वे पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, थर्मल पावर और ग्रीन एनर्जी सब एक साथ कर रहे हैं। 2014 में उनका मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ था जो 2025 तक कई गुना हो गया। यह सबसे तेज ग्रोथ है। लेकिन इतना सेंट्रलाइजेशन नया नहीं है। पुराने जमाने में ब्रिटिश कंपनियां भी बड़े-बड़े काम करती थीं। आज सरकार PPP मॉडल दे रही है जिससे अडानी जैसे ग्रुप को मौका मिला। असली बात यह है कि उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी सब कुछ खुद संभालने की क्षमता ने उन्हें आगे किया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि एक ग्रुप का इतना दबदबा कंपटीशन कम कर सकता है। दुनिया में भी अमेरिका या चीन में बड़े प्लेयर्स हैं लेकिन वहां रेगुलेशन मजबूत है। भारत में भी SEBI और CCI जैसी संस्थाएं नजर रख रही हैं। यह सेंट्रलाइजेशन अच्छा है क्योंकि इंफ्रा जल्दी बन रहा है लेकिन बैलेंस जरूरी है।

आगे क्या होगा-फायदे और चुनौतियां

भविष्य में अडानी ग्रुप का विकास भारत को नई ऊंचाई दे सकता है। वे 100 बिलियन डॉलर AI एनर्जी प्लान पर काम कर रहे हैं जो डेटा सेंटर्स और ग्रीन पावर को जोड़ेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, बिजली सस्ती होगी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन चुनौतियां भी हैं। कोयला पावर बढ़ाने से पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। एक ग्रुप पर इतना निर्भर होना सप्लाई चेन में रिस्क ला सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे प्लेयर्स भी मौका पाएं और कीमतें फेयर रहें। अडानी का फोकस अब ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट मीटर पर है जो भविष्य की जरूरत है। कुल मिलाकर फायदे ज्यादा लगते हैं अगर बैलेंस बना रहे। आम आदमी के लिए बेहतर रोड, एयरपोर्ट, सस्ती बिजली और क्लीन एनर्जी का सपना हकीकत बनेगा। लेकिन लंबे समय में सस्टेनेबल ग्रोथ तभी संभव है जब कंपटीशन और रेगुलेशन मजबूत रहे। अडानी की कहानी भारत की कहानी है -तेज विकास लेकिन सावधानी के साथ।

500-600 रुपये की फीस, खाली हॉस्टल और नाम बदलते स्कूल

बच्चों की पढ़ाई क्यों बनी राजनीति का शिकार

@ पार्थ सारथी

देश की आजादी को लगभग उन्यासी साल होने वाले हैं। आजादी के अहम उद्देश्य में से एक सबको शिक्षा मुहैया कराना भी है। स्वतंत्र भारत की चुनी पहली सरकार ने ही 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया था।1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तब से लगातार शिक्षा को सर्वसुलभ बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे- प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि सस्ते और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए,लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक के साथ ही साथ बहुदलीय होने के कारण सत्ता का भी परिवर्तन होता है। सिर्फ सत्ता का ही परिवर्तन नहीं होता बल्कि राजनैतिक विचारों का भी परिवर्तन होता है। जिसके वजह से कई कल्याणकारी योजनाओं को नुकसान भी होता है। वह राजनीति का भी शिकार हो जाते हैं।

इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। साल था 2014-15। सरकार समाजवादी पार्टी की मुखिया थे -अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में बेहतर और निशुल्क शिक्षा देने के लिए एक नई योजना लाई गई। हर मंडल में एक विद्यालय खोले जाने थे। योजना के मुताबिक विद्यालय खोले भी गए। विद्यालय में शिक्षा, स्कूली ड्रेस, हॉस्टल की व्यवस्था, कॉपी-किताब – सब कुछ मुफ्त था। विद्यालय का नाम समाजवादी अभिनव मॉडल स्कूल रखा गया। जमीन का अधिग्रहण हुआ, बिल्डिंग बनी। क्षेत्रीय विधायक संतोष पांडेय ने इसका उद्घाटन भी किया। विद्यालय चल पड़ा लेकिन कुछ समय बाद सरकार बदल गई। सरकार बदली और स्कूल का हाल बदल गया। विद्यालय, जिसमें हर विषय के सरकारी अध्यापक, प्राचार्य, बाबू होने थे, जिसमें पूरी व्यवस्था निःशुल्क होनी थी// वह पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो गया।सबसे पहले तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्यालय का नाम बदल दिया। अब यह प्रधानमंत्री श्री विद्यालय के नाम से जाना जाता है।लेकिन नाम बदलने से बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में न तो पर्याप्त सरकारी अध्यापक हैं, न ही कर्मचारी, यहां तक कि प्राचार्य तक नहीं हैं।

वर्तमान समय में कुल मिलाकर 2-3 सरकारी कर्मचारी हैं -अध्यापक, बाबू और चपरासी मिलाकर।विद्यालय, जिसे पूरी तरह से निःशुल्क होना था, आज वहाँ लगभग 500-600 रुपए तक फीस देना पड़ता है। छात्रों को अपने ड्रेसेस खुद खरीदनी पड़ती हैं। हॉस्टल तो बना है, पर वह किसी काम का नहीं है। विद्यालय में लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, और बच्चों को कॉपी तथा किताबें स्वयं खरीदनी पड़ती हैं।

रिपोर्ट को समझिए एक शिक्षक की आंखों से

हम जब उस विद्यालय के पास पहुंचे, तो मैदान के किनारे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी टोपी को हाथ में मसल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यहां पढ़ने आए बच्चों के पिता हैं, तो उन्होंने धीरे-धीरे जवाब दिया

कि यह विद्यालय पहले बहुत अच्छा था मेरे बेटे को सब मुफ्त मिलता था। ड्रेस, किताब, सब कुछ पर अब कहां सब गया ?उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन आँखों में वह निराशा साफ दिख रही थी जो हार मान लेने की नहीं, बल्कि लड़ते रहने की शिकायत थी।कई अभिभावक सुबह-सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए और फिर वहीं बातचीत में शामिल हो गए। इन अभिभावकों ने बताया कि पहले स्कूल की व्यवस्था ठीक थी। बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलती थीं, ड्रेस मिलती थी, हॉस्टल भी ठीक चलता था और पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देना बच्चों के लिए सरल था।लेकिन नाम बदलते ही सबकुछ बदल गया। शिक्षकों की कमी, सुविधाओं की गिरावट और साथ ही फीस का अतिरिक्त बोझ ने गरीब परिवारों को परेशान कर दिया है।

एक छात्रा ने बताया कि कैसे उसका सपना टूटा

हमारी मुलाकात उसी विद्यालय की एक 9वीं की छात्रा रुचिका (बदला हुआ नाम) से हुई। छोटी-सी लड़की, स्कूल की पुरानी बेल्ट पहने, आंखों में उम्मीद अभी भी थी।पहले जब विद्यालय में सब मुफ्त मिलता था, तो मम्मा ने कहा था- 'तू पढ़कर बड़े शहर में नौकरी करेगी। हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, पर तुम पढ़ाई करोगी।' आज मुझे 500-600 रुपए फीस देना पड़ता है मेरे पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं पैसे देना मुश्किल हो रहा है।वह रुचिका जितनी छोटी है, उतनी ही उसकी चिंता बड़ी-बड़ी है। उसके शब्दों में ज़िन्दगी की गहरी समझ थी -अगर फीस और किताबें महंगी होगी तो पढ़ाई बीच में रुक जाएगी।"इन शब्दों में केवल एक बच्ची का डर नहीं – देश की शिक्षा नीति के पीछे का असल दर्द झलका।

विद्यालय के पास बैठे अध्यापक से बातचीत में पता चला कि मूल समस्या क्रमिक बदलाव और राजनीतिक प्राथमिकताओं में फेरबदल है।पहले स्कूल को समाजवादी सरकार का विशेष समर्थन मिला था," उन्होंने कहा। "लेकिन जैसे ही सरकार बदली, शिक्षा-व्यवस्था में प्राथमिकता गिरने लगी। अब स्कूल को नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री स्कूल, पर सुविधा वही पुरानी-सी रह गई। न तो पुस्तकें मुफ्त हैं, न प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त हैं, और न ही छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हैं।शिक्षक के शब्दों में निराशा थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी कि सही दिशा में कोई पहल होगी तो स्थिति सुधर सकती है।उन्होंने बताया कि अब लगभग 80% छात्रों के माँ-बाप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई ना कोई फीस जमा कराते हैं। यदि फीस नहीं दी जाती है, तो स्कूल ही पढ़ाने से इनकार कर देता है।यह वह बदलाव है शिक्षा का व्यापार बनना, जिसका उद्देश्य मूल रूप से बच्चों को शिक्षित करना था।

एक और परिवार की कहानी

हमने उसी शहर के एक छोटे-से मोहल्ले में किरण और राजेश से बातचीत की। छोटे-से कमरे में किराए पर रहने वाले राजेश का कहना था हमारे लिए शिक्षा मुफ्त होना एक सपना था। पहले जब सब मुफ्त मिलता था, तो मैं खुश होता था। बेटी को स्कूल भेजता था, क्योंकि कमाई कम है। पर अब ऐसा नहीं हो पाता। 500-600 रुपए फीस मेरे जैसे परिवार के लिए बड़ी रकम है।किरण (बदला हुआ नाम) एक घरेलू सहायिका, जो रोज़-मर्रा का काम करके घर का खर्च चलाती हैं, कहती हैं -हमने उम्मीद की थी कि सरकारी स्कूल हमारे बच्चों को बेहतर जीवन दे पाएंगे। पर अब वही स्कूल फीस मांगने लगा है। किताबें-कॉपी सब हमें खुद खरीदना पड़ता है। शिक्षा अब पहले जैसी निशुल्क नहीं रही।उन दोनों के शब्दों में थकान, चिंता, और भविष्य की अनिश्चितता स्पष्ट थी। छोटे-से कमरे की दीवार पर टंगी हुई बच्चों की चित्रकारी यह बताती थी कि हर बच्चा सपना देखता है, पर पूरा होते-होते वह बिखर जाता है।

राजनीतिक बदलाव या शिक्षा में विफलता?

2022-23 में जब यह सरकारी स्कूल समाजवादी अभिनव मॉडल स्कूल के रूप में खोला गया, तो माता-पिता, विद्यार्थी और क्षेत्रीय नेताओं ने इसे शिक्षा की क्रांति बताया था।वादा यह किया गया था कि शिक्षा पूरी तरह निशुल्क रहेगी -ड्रेस, किताब, हॉस्टल, सब मुफ्त मिलेगा। पर 2026 आते-आते हर वह चीज़ जो शिक्षा को समर्थ बनाती थी, या तो फीकी पड़ गई है या गायब हो गई है।राजनीतिक विचारों के बदलाव ने उस योजना को क्षति पहुँचाई है जो शिक्षा के नाम पर शुरू की गई थी। नतीजा

> शिक्षा केवल स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं है, यह बच्चों के सोचने-समझने की क्षमता, उनके आत्म-विश्वास और भविष्य की दिशा को आकार देती है। जब शिक्षा योजना राजनीति की दौड़ का हिस्सा बन जाती है, तो उसका मूल उद्देश्य ,सबको गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क शिक्षा देना खोने लगता है। एक बार जब यह उद्देश्य कमजोर पड़ता है, तो समाज की सबसे संवेदनशील शक्ति, यानी बच्चे, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
>
> **स्नेह वीर पुंडीर (शिक्षा विशेषज्ञ)**

यह है कि आज वही बच्चों की उम्मीदें फीस, किताबों और सुविधाओं की कमी में उलझ कर रह गई हैं।

आखिर माजरा क्या है?

स्थानीय अभिभावकों का मानना है कि यह समस्या अकेले इस विद्यालय तक सीमित नहीं है।जहाँ भी परिवर्तन और राजनीतिक बदलाव हुआ है, वहाँ पर योजना का मूल उद्देश्य खो गया है," एक अभिभावक ने कहा। "हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पर व्यवस्था भी बच्चों के साथ खड़ी नहीं दिखती।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को योजना के मूल लक्ष्य -निःशुल्क, गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा -को पुनः लागू करने की ज़रूरत है।

समस्या की जड़ है नीतिगत अस्थिरता

शिक्षा नीतियों के विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में एक स्थिर शिक्षा नीति की कमी है। राजनीतिक बदलाव के साथ ही योजनाओं में फेर-बदल होता रहता है, जिससे कार्यान्वयन बाधित हो जाता है।शिक्षा विशेषज्ञ स्नेह वीर पुंडीर कहते हैं कि कोई योजना स्थिर नीतिगत दिशा में न चली, बल्कि हर 5 साल में बदलती रहे, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। बच्चों की शिक्षा जीवन-पर्यन्त निवेश है। उसे राजनीति की बारीकियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।उनके अनुसार, राजनीतिक बदलाव और शिक्षा योजनाओं की अस्थिरता के कारण आज स्थिति वही है। कागज़ों में तो योजनाएं शानदार हैं, पर जमीन पर छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है।समाजवादी अभिनव मॉडल स्कूल का उदाहरण यह बताता है कि यदि शिक्षा नीति राजनीतिक विचारों के फेर-बदल से प्रभावित होती रहे, तो उसका लक्ष्य खो जाता है।शिक्षा केवल सरकारी योजना नहीं है। यह एक बच्चे के जीवन, एक परिवार के सपने, और एक समृद्ध समाज की नींव है।जहाँ एक ओर भारत ने शिक्षा के विस्तार में कई दशक में प्रगति की है, वहीं जहाँ-जहाँ राजनीति की बिसात बदलती है, वहाँ-वहाँ शिक्षा के मूल लक्ष्य खोते नजर आते हैं।

डॉलर के दबाव में रुपया 95 पार

आम आदमी की जेब और देश की महंगाई पर बढ़ता संकट

रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर मजबूती से बढ़ रहा है। भारतीय मुद्रा ने काफी हद तक अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में यह कोई अत्यधिक चिंताजनक बात नहीं है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि डॉलर का मजबूत होना एक वैश्विक रुझान है।

निर्मला सीतारमण (केंद्रीय वित्त मंत्री)

रुपये का हाल यह दिखाता है कि भारतीय मुद्रा का मूल्य भाजपा सरकार के तहत गिर रहा है। मुद्रा की गिरावट के पीछे सरकार की अर्थव्यवस्था-प्रबंधन नीतियाँ और बढ़ती विदेशी निवेश की निकासी प्रमुख हैं। सवाल उठता है कि जब भारत को व्यापार, निवेश और आर्थिक स्थिरता की जरूरत है, तब यह गिरावट क्या संकेत दे रही है?

मल्लिकार्जुन खड़गे (कांग्रेस अध्यक्ष)

रुपया का निरंतर गिरता स्तर यह बयान करता है कि मौजूदा नीतियों से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। मुद्रा-सक्रियता को संभाला जाना चाहिए और सरकार को स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था-प्रबंधन के बारे में आम जनता को आश्वस्त करना चाहिए, न कि केवल बड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए।

प्रियंका गांधी (कांग्रेस नेता)

ईरान युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय करेंसी को झकझोर दिया, आम परिवारों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

- रुपया 95 पार, आम आदमी की जेब पर दबाव
- तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई का नया झटका
- विदेशी निवेशक बिकवाली, बाजार में अस्थिरता
- RBI कदम उठा रहा, लेकिन चुनौती अभी दूर नहीं
- निर्यातकों को फायदा, आम परिवार को नुकसान

@ रिंकू विश्वकर्मा

30 मार्च 2026 का दिन भारतीय वित्तीय बाजारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 95 के स्तर को पार कर गया। कारोबार के दौरान रुपया 95.22 तक गिर गया, जो पिछले कई वर्षों में रिकॉर्ड नीचले स्तर पर पहुंचने के बराबर है। हालांकि, दिन के अंत तक रुपये ने थोड़ा संभलते हुए 94.78 पर कारोबार बंद किया। लेकिन यह मामूली मजबूती भी आम आदमी के लिए राहत की खबर नहीं है।रुपए की कमजोरी का असर सबसे पहले आम परिवार की जेब पर पड़ेगा। सोचिए, रोजमर्रा के खर्च, पेट्रोल-डीजल, गैस, मोबाइल, लैपटॉप और विदेश से आयात होने वाले सामानों की कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अब इनकी लागत और बढ़ जाएगी। पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि, इम्पोर्टेड मोबाइल और लैपटॉप के दाम और सोना-चांदी की बढ़ती कीमतें सीधे आम आदमी के बजट को प्रभावित करेंगी।

तेल महंगा, डॉलर की मांग बढ़ी

रुपए में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच युद्ध के कारण तेल की सप्लाई अनिश्चित हो गई है। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के 20 प्रतिशत और भारत के आधे तेल की सप्लाई के लिए अहम मार्ग है, अब तनावपूर्ण स्थिति में है। इस इलाके में किसी भी तरह की बाधा आने की संभावना से ब्रेंट क्रूड की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं।भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल आयात करता है और भुगतान डॉलर में करता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ी, और रुपया कमजोर हुआ। इस वित्तीय वर्ष में रुपया पहले ही लगभग 10 प्रतिशत कमजोर हो चुका है। सिर्फ पिछले महीने ही इसका मूल्य 4 प्रतिशत गिर चुका है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है।मार्च में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों की बजाय अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं। इस भारी बिकवाली ने भारतीय करेंसी पर दबाव बढ़ा दिया है।

RBI ने उठाए कदम, लेकिन चुनौती बनी हुई है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंकों के लिए रातभर डॉलर जमा रखने की सीमा घटाकर 100 मिलियन डॉलर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि बैंक अपने अतिरिक्त डॉलर को बाजार में बेचेंगे, जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपए को मजबूती मिल सकती है।लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक तेल महंगा रहेगा और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहेगी, रुपया अस्थिर बना रहेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि यदि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ, तो रुपए की गिरावट 98 तक भी जा सकती है।

अमीर नहीं, आम आदमी प्रभावित

रुपए की कमजोरी का असर सिर्फ बड़े उद्योगों या तेल कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, रोजमर्रा की चीजों की महंगाई, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के खर्च यह सब सीधे आम परिवार की जेब पर असर डालते हैं।छोटे व्यापारियों और उद्योगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे आम कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम होगी और आर्थिक गतिविधियों में भी मंदी आ सकती है।

कुछ उद्योगों को फायदा भी

रुपए की कमजोरी से कुछ क्षेत्रों को फायदा भी होगा। निर्यातक उद्योगों को इसका लाभ मिलता है। आईटी सेक्टर, फार्मा और कपड़ा उद्योग की कंपनियों को अपने उत्पादों या सेवाओं के बदले डॉलर मिलते हैं। जब वे डॉलर को रुपए में बदलते हैं, तो उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा रुपए मिलते हैं। इससे उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होती है और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं।

करेंसी वैल्यू कैसे तय होती है

किसी भी देश की करेंसी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। यदि भारत को ज्यादा तेल और अन्य सामान आयात करने की जरूरत है, तो डॉलर की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ी और सप्लाई सीमित रही, तो डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर होगा।देश की महंगाई दर, ब्याज दरें और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी रुपए की वैल्यू तय करता है। यदि भारत में ब्याज दरें आकर्षक हों और अर्थव्यवस्था स्थिर हो, तो विदेशी निवेशक डॉलर लेकर भारत आएंगे, जिससे रुपए की सप्लाई बढ़ेगी और मजबूती आएगी।

महंगाई का दबाव, विकास पर असर

तेल और डॉलर की कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, परिवहन की लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे जीवन यापन की लागत बढ़ेगी और आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है।विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति का असर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ने से घरेलू क्रय शक्ति कम होगी और निवेश धीमा पड़ सकता है। ब्याज दरें भी कम करना मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई और रुपए की कमजोरी को संतुलित करना जरूरी है।

सरकारी और RBI की जिम्मेदारी कितनी ?

रुपा कमजोर होने से आम परिवारों में तनाव बढ़ता है। परिवारों को बजट पर पुनर्विचार करना पड़ता है। विदेश यात्रा, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च और दैनिक जरूरतें महंगी हो जाती हैं। व्यापारियों के लिए उत्पादन लागत बढ़ती है और ग्राहकों की क्रय शक्ति कम होने के कारण बिक्री में भी असर पड़ सकता है। बाजार में स्थिरता बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रित करना और आम आदमी की जेब पर दबाव कम करना प्राथमिकता बन जाती है। सरकार को अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी।

स्त्रियाँ यात्रा-वृत्तांत नहीं लिखतीं

मेरे देश में
हर दिन सतासी औरतों की

अस्मिता
तार-तार कर दी जाती है—

हर पंद्रह मिनट में एक
और हज़ारों औरतें

ख़ुद को अपराधी मान
घर की दीवारों में छिप जाती हैं

भय की एक लक्ष्मण-रेखा
गाँव की हद पर खींच दी गई है

शाम के धुँधलके से पहले
आँगन में बंधक हो जाना

उसने जीवन की शर्त की तरह
स्वीकार कर लिया है

कहा जाता है—
ऐसी औरतों की

इज़्ज़त नहीं होती
क्योंकि

उसकी इज़्ज़त का बटुआ
कोई पुरुष लूट ले गया है

उसे बचाने के लिए
वह क़ायदों की दहलीज़ में

ख़ुद को बाँध लेती है
बेतरह शराब पीते लेखक

हिकारत से कहते हैं—
'स्त्रियाँ अच्छे यात्रा-वृतांत नहीं लिखतीं...'

वे भूल जाते हैं—
नई जगह की हर यात्रा में

हर दिन की
उन सतासी औरतों में

वह भी हो सकती है
इनबॉक्स में अजनबी पुरुष

नंगी तस्वीरें भेजते हैं
दिन-दहाड़े पैंट की ज़िप खोल

पौरुष दिखाते मर्द देखे हैं उसने
सुनसान सड़क से गुज़रते हुए

कितनों ने उसके वक्ष और नितंबों पर
हाथ फेरकर भाग जाना सीखा है

किसी अजनबी यात्रा पर निकलने से
पहले
वह सुरक्षा सोचती है

फिर व्यंग्य से पूछा जाता है—
'स्त्रियाँ क्रांति क्यों नहीं लिखतीं?'

बहू-बेटियों की आँखों में
लिहाज़ का काजल आँजवाकर,

होंठों पर ख़ामोशी की लाली सजाकर—
चूल्हा, चकला, बेलन, बच्चा,

रिश्तेदारी, त्योहार, अचार,
बीमार-अज़ारी,

चहारदीवारी की ज़िम्मेदारी...
क्या पहली मार्क्सवादी क्रांति

पति, भाई, पिता के ख़िलाफ़
वह लिखेगी?

वह लिखती है
यात्रा-वृत्तांत—

आँगन से झाँकते आकाश का,
छत से गुज़रते मौसम का,

खिड़की से झूलते चाँद का
मनमाफ़िक एक क़दम भी

डायरी में दर्ज करती है
तुमने किताबों में जीवन-दर्शन पढ़ा है

उसने अपने गर्भ में जीवन गढ़ा है
तुमने पीड़ा लिखी है—

उसने उसे पल-पल जिया है
स्त्री-क़लम लंबे समय तक

हाशिए में बाँध दी गई—
महादेवी वर्मा,

शिवानी
या

मन्नू भंडारी बनकर
वह लिखती रही—

झरोखों से दिखती दुनिया,
आँगन के किरदारों के आख्यान,

कभी गिल्लू तो कभी भक्तिन,
कृष्णकली की भीगी कथा,

पूतोंवाली का दारुण जीवन,
या बंटी के बालमन की उलझनें

फिर भी सदियों से कहा जाता रहा—
'औरतें यायावर नहीं होतीं...'

वह कैसे रचे
'मेरी तिब्बत यात्रा'-सी यात्रा

आधी रात
सूनी पहाड़ियों के

जीवंत सन्नाटों का अनुभव?
वह कभी नहीं कर पाएगी—

'वह भी कोई देस है महराज!'
क्योंकि उसे इज़्ज़त का बटुआ सँभालना है

इसलिए वह लिखती है
कमरे के एकांत का साहित्य—

नम कहानियाँ,
रिश्तों की पीड़ा की कविताएँ,

कुनबे से विद्रोह का राग,
देह से परे अस्तित्व की छटपटाहट।

जो बनीं—
गार्गी,

महादेवी वर्मा,
तसलीमा नसरीन,

अमृता प्रीतम,
अरुंधति रॉय,

या
बेबी हालदार—

याद रखना,
उन्होंने सबसे पहले छोड़ी थी

तुम्हारी 'अनुगामिनी' होने की शर्त।

मेरे शहर से लौटती ट्रेन

मेरे शहर से लौटते वक़्त
ट्रेन हौले-हौले

प्लेटफ़ॉर्म छोड़ने लगती है
मेरा शहर

नज़रों के दायरे से
धीरे-धीरे फिसलने लगता है

प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े
अनजान चेहरे

अपने ही में मशग़ूल—
ठेले, खोमचे, टोकरियाँ,

अख़बार बेचता लड़का
खिड़की के पास से

हर नज़ारा गुज़रने लगता है
मेरी रुख़सत से बेपरवाह

ये सारे लोग
कल भी

यहीं की गलियों में घूमेंगे
ये वे ख़ुशनसीब हैं

जो अपने शहर में रहते हैं
ट्रेन ने पकड़ ली रवानी—

धीमे-धीमे
हिचकोले खाते हुए

मैं खिड़की से गुज़रते
ज़र्रे-ज़र्रे को

डबडबाई आँखों में
भर लेने की कोशिश में हूँ

ओझल हो गया
'जंक्शन' के साथ लिखा

मेरे शहर के नाम वाला
पीली रंगत का रेलवे-बोर्ड

जैसे पैरों के नीचे से
ज़मीन खिसक गई हो

साथ-साथ चलते
प्लेटफ़ॉर्म से भी

रिश्ता टूटता है
पटरियों की सरपट के साथ

धागे ढीले होते जाते हैं
दुकानें,

बिजली के खंभे,
धीरे-धीरे ओझल

विपरीत दिशा में दौड़ती
जानी-पहचानी

बदरंग इमारतें
छूटती जाती हैं

मेरी तफ़रीह वाली सड़कें,
मंदिर,

बाज़ार...
दूर मैदान में खेलते बच्चे—

बेअसर इस बात से
कि कोई इस शहर में अपनी जड़ें छोड़

कटने का गहरा घाव लिए
बहुत दूर जा रहा है

कभी मैं यहाँ रहती थी
अब

यह
शहर

मेरे
भीतर

रहता
है

जब मेरे शहर से लौटती ट्रेन छूटती है।

मधु चतुर्वेदी
नई पीढ़ी की कवि-लेखक। चार पुस्तकें प्रकाशित।

सुंदरबन: जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच जाल फेंकते हैं मछुआरे

बाघ का खतरा, बढ़ता समुद्र और भूख की मजबूरी-एक ऐसा संघर्ष, जहां इंसान हर रोज जीने के लिए मौत से समझौता करता है

- यहां जंगल सिर्फ घर नहीं, हर दिन की परीक्षा है-जहां एक गलती जिंदगी छीन सकती है।
- बाघ का डर बड़ा है, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा ताकतवर है।
- सुंदरबन में हर नाव सिर्फ मछली नहीं, उम्मीद और खतरा दोनों लेकर लौटती है।
- यह संघर्ष सिर्फ इंसान बनाम प्रकृति नहीं, बल्कि अस्तित्व बनाम मजबूरी की कहानी है।
- जहां बाकी दुनिया जीती है, वहां सुंदरबन के लोग हर दिन बचने की कोशिश करते हैं।

सुंदरबन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है जो भारत और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ है। यहां बंगाल के बाघ रहते हैं और इंसान भी अपनी रोजी-रोटी के लिए इस जंगल पर निर्भर है। करीब 50 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं और उनमें से बहुत से मछुआरे हैं जो नाव लेकर जंगल की नदियों और खाड़ियों में मछली और केकड़े पकड़ने जाते हैं। ये लोग सुबह जल्दी उठकर नाव पर निकल पड़ते हैं क्योंकि यही उनका मुख्य काम है। जंगल की मिट्टी नमक वाली है इसलिए खेती ज्यादा नहीं होती और मछली पकड़ना ही परिवार को खाना-कपड़ा देता है। लेकिन ये जंगल सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। बाघ यहां इंसान को शिकार समझते हैं। हर साल कई मछुआरे बाघ के हमले में घायल या मारे जाते हैं। फिर भी ये लोग यहां से नहीं जाते क्योंकि बाहर दूसरा काम आसानी से नहीं मिलता। जलवायु बदलाव से समुद्र का पानी बढ़ रहा है और तूफान ज्यादा आ रहे हैं जिससे गांव डूबते हैं। मछुआरे जानते हैं कि जंगल उन्हें बचाता भी है और खतरा भी देता है। फिर भी वे हर दिन नाव लेकर निकलते हैं क्योंकि परिवार को भूखा नहीं छोड़ सकते। कुछ युवा बाहर काम ढूंढने चले जाते हैं लेकिन बूढ़े और औरतें यहां ही रहकर परिवार संभालती हैं। सुंदरबन की ये जिंदगी आसान नहीं है। यहां इंसान को हर वक्त सावधान रहना पड़ता है। बाघ चुपके से आता है और मछुआरा अकेला होता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। सरकार कुछ मदद करती है लेकिन काफी नहीं। मछुआरे बताते हैं कि वे जंगल से डरते हैं लेकिन पेट की आग से ज्यादा डरते हैं। इस जंगल में रहना सिर्फ जीना नहीं बल्कि हर रोज बचने की कोशिश भी है।

सुंदरबन का रहस्य: जहां इंसान और बाघ एक साथ सांस लेते हैं

सुंदरबन में मछुआरों की जिंदगी सुबह से शुरू होती है। वे छोटी नाव पर बैठकर जंगल की संकरी नदियों में जाते हैं जहां पानी कम होता है। वहां वे जाल बिछाते हैं या केकड़े पकड़ने के लिए छेद खोदते हैं। कभी-कभी वे शहद भी इकट्ठा करते हैं लेकिन मुख्य काम मछली पकड़ना है। दिन भर नाव पर रहते हैं और शाम को घर लौटकर मछली बाजार में बेचते हैं। पैसे मिलते हैं तो परिवार को चावल और दाल मिल जाता है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। जंगल में बाघ घूमते रहते हैं और वे तैर भी सकते हैं। मछुआरे बताते हैं कि बाघ इतनी चुपके से आता है कि आवाज तक नहीं सुनाई देती। कई बार वे अकेले जाते हैं क्योंकि टीम बनाकर जाना महंगा पड़ता है। नाव छोटी होती है और जाल महंगे होते हैं। कुछ मछुआरे बिना परमिट के जंगल में जाते हैं क्योंकि परमिट लेना मुश्किल और महंगा है। फिर भी वे जाते हैं क्योंकि परिवार का पेट भरा रहे। घर लौटकर वे थके हुए होते हैं लेकिन बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि जंगल कैसे खतरा देता है। गांव में औरतें घर संभालती हैं और कभी-कभी वे भी जंगल जाती हैं लेकिन कम। जलवायु बदलाव से मछली कम हो रही है इसलिए उन्हें गहरे जंगल में जाना पड़ता है जहां खतरा ज्यादा है। फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। वे कहते हैं कि सुंदरबन उनका घर है। यहां रहकर वे बाघ के साथ जीना सीख चुके हैं। कुछ परिवारों में बाघ ने पति या बेटे को ले लिया लेकिन फिर भी वे जंगल से दूर नहीं होते। ये जिंदगी सिर्फ कमाई की नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारी की भी है। मछुआरे हर दिन प्रार्थना करते हैं कि आज सुरक्षित लौट आएं।

बाघ के हमले और परिवार का दर्द

सुंदरबन में बाघ के हमले आम बात है। २०२५ और २०२६ में कई घटनाएं हुईं जहां मछुआरे बाघ का शिकार बने। नवंबर २०२५ में एक मछुआरे को बाघ ने घसीट लिया और अगले दिन उसका शरीर मिला। फरवरी २०२६ में भी एक और मछुआरा गायब हो गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर साल करीब १० से २५ लोग मारे जाते हैं जबकि कुछ कहते हैं कि १०० तक हमले हो सकते हैं। आधिकारिक आंकड़े कम दिखाते हैं क्योंकि कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं होतीं। मछुआरे बिना अनुमति जाते हैं तो डरते हैं कि पुलिस पकड़ेगी। बाघ चुपके से हमला करता है और गर्दन पकड़कर घसीट ले जाता है। बचने वाले कहते हैं कि वे लड़ते हैं लेकिन ताकत कम पड़ जाती है। परिवार में दर्द बहुत होता है। पत्नी और बच्चे अकेले रह जाते हैं। बांग्लादेश में ऐसी विधवाओं को 'बाघ की विधवा' कहकर दूर कर दिया जाता है। भारत में भी मदद कम मिलती है। सरकार कुछ मुआवजा देती है लेकिन वो काफी नहीं। परिवार का सहारा चला जाता है और बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। फिर भी मछुआरे रुकते नहीं। वे कहते हैं कि बाघ जंगल का राजा है और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ जगहों पर स्मार्ट डरावने लगाए गए हैं जो आवाज करते हैं और बाघ को दूर रखते हैं। सौर्य लाइट और जाल भी लगाए गए हैं। लेकिन जंगल इतना बड़ा है कि हर जगह सुरक्षा नहीं हो सकती। ये हमले सिर्फ मौत नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देते हैं। मछुआरे जानते हैं कि खतरा है लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे एक-दूसरे को चेतावनी देते हैं और साथ मिलकर जंगल जाते हैं। फिर भी हर बार जब कोई नाव लौटती है तो गांव में राहत की सांस निकलती है।

जलवायु बदलाव और रोजमर्रा की मुश्किलें

सुंदरबन में मछुआरों की जिंदगी सिर्फ बाघ से नहीं बल्कि तूफान और नमक वाले पानी से भी प्रभावित है। समुद्र का पानी बढ़ रहा है जिससे खेती खराब हो रही है। मछली भी कम हो गई है इसलिए उन्हें गहरे जंगल में जाना पड़ता है। हर साल दो महीने मछली पकड़ने पर पाबंदी लगती है ताकि मछली बढ़े लेकिन इस दौरान परिवार को खाना नहीं मिलता। सरकार मदद की घोषणा करती है लेकिन कई बार वो नहीं पहुंचती। गरीबी बहुत है। ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। वे साहूकारों से कर्ज लेते हैं और ब्याज चुकाने के लिए ज्यादा मछली पकड़ते हैं। तूफान आने पर नाव डूब जाती है और घर बह जाते हैं। २०२४-२५ के तूफानों ने बहुत नुकसान किया। फिर भी लोग जंगल से दूर नहीं जाते क्योंकि बाहर काम नहीं मिलता। युवा केरल या तमिलनाडु चले जाते हैं लेकिन बूढ़े यहीं रहते हैं। जंगल उन्हें सुरक्षा भी देता है क्योंकि मैंग्रोव तूफान रोकते हैं। लेकिन नियम सख्त हैं। बोट लाइसेंस महंगा है और जंगल विभाग की पाबंदी से लोग परेशान हैं। कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार भी है। मछुआरे कहते हैं कि हम जंगल का सम्मान करते हैं लेकिन पेट भी भरना है। जलवायु बदलाव से सब बदल रहा है। नमक पानी बढ़ने से मछली की प्रजाति कम हो रही है। फिर भी वे कोशिश करते हैं। कुछ गांवों में सहकारी समितियां बनाई गई हैं जो सस्टेनेबल तरीके से मछली पकड़ने में मदद करती हैं। लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। ये लोग हर दिन संघर्ष करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि सुंदरबन उनका घर है और वे इसे छोड़कर नहीं जा सकते।

सरकार और समुदाय के कदम

सुंदरबन में मछुआरों की जिंदगी मुश्किल है लेकिन उम्मीद भी है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। स्मार्ट डरावने लगाए गए हैं जो बाघ को गांव से दूर रखते हैं। सौर्य लाइट और जाल भी मदद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर वैकल्पिक काम सिखाए जा रहे हैं जैसे पर्यटन या सस्टेनेबल खेती। एनजीओ मछुआरों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे कम खतरे में मछली पकड़ सकें। मैंग्रोव लगाने के कार्यक्रम चल रहे हैं जो तूफान रोकते हैं और मछली बढ़ाते हैं। मछुआरे खुद समुदाय बनाकर मदद करते हैं। वे एक-दूसरे को चेतावनी देते हैं और घायल साथी की मदद करते हैं। कुछ परिवार अब बाघ के हमले के बाद भी हिम्मत रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार मुआवजा देती है और स्कीम चलाती है लेकिन उसे और बेहतर बनाना होगा। बांग्लादेश और भारत दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि जंगल दोनों का है। मछुआरे कहते हैं कि अगर सुरक्षा बढ़े और मदद मिले तो वे बेहतर तरीके से जी सकेंगे। वे जंगल से प्यार करते हैं और उसे बचाना भी चाहते हैं। जलवायु बदलाव से लड़ने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। ये लोग सिर्फ बच नहीं रहे बल्कि जीने की कोशिश भी कर रहे हैं।

क्या वामपंथ फिर उठेगा, या इतिहास बनकर रह जाएगा?

युवा चेहरे, रोजगार का मुद्दा और जमीनी संघर्ष-लेफ्ट की वापसी की कोशिश, लेकिन क्या बदल पाएगा सियासी समीकरण?

कभी सत्ता का शिखर, आज संघर्ष की जमीन-वामपंथ की असली परीक्षा अब है।

इतिहास मजबूत है, लेकिन क्या वर्तमान उसे स्वीकार करने को तैयार है?

युवा चेहरों का जोश बनाम गिरता जनाधार-किसका पलड़ा भारी पड़ेगा?

सिर्फ विचार नहीं, अब जमीन पर पकड़ साबित करने की चुनौती है।

बंगाल तय करेगा-वामपंथ वापसी करेगा या सियासत के हाशिये पर चला जाएगा।

बंगाल में वामपंथ यानी लेफ्ट फ्रंट ने लंबे समय तक सत्ता संभाली थी। 1977 से 2011 तक पूरे 34 साल तक सीपीआईएम के नेतृत्व में यह गठबंधन सरकार चलाता रहा। उस वक्त ज्योति बसु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेता राज्य को नई दिशा देते थे। स्कूल-कॉलेज, जमीन सुधार और गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई गईं। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद वामपंथ का सफर मुश्किल हो गया। 2021 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत पाए। वोट शेयर 39 प्रतिशत से गिरकर सिर्फ 5 प्रतिशत के आसपास रह गया। अब 2026 के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट दोबारा जोर आजमा रहा है। मार्च 2026 में उन्होंने पहले 192 उम्मीदवारों की सूची जारी की, फिर 32 और जोड़े, कुल 224 से ज्यादा हो गए। सीपीआईएम, आरएसपी, सीपीआई, एआईएफबी जैसे पार्टियां साथ हैं। साथ ही सीपीआईएमएल लिबरेशन को 10 सीटें दी गईं और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ बातचीत चल रही है। कांग्रेस अलग लड़ रही है। लेफ्ट अब युवा और ग्रासरूट लीडरों पर दांव खेल रहा है। राज्य में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, करीब 1.25 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में बाहर चले गए। लेफ्ट इसे अपना मुद्दा बना रहा है। अभी चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे। वामपंथ की पुरानी ताकत कम हुई है, लेकिन नए चेहरों और मुद्दों से कुछ उम्मीद जगी है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह वापसी का मौका है या सत्ता का पुराना दौर हमेशा के लिए चला गया। इस बार 57 सीटें ऐसी हैं जहां 2021 में 8000 वोट से भी कम अंतर था। छोटी सी बदलाव से नतीजे पलट सकते हैं। लेफ्ट की कोशिश है कि युवा और गरीब वोटर फिर से उनके पास आएं।

चर्चा के केंद्र में ये वामपंथी नेता

इस बार वामपंथी नेता काफी चर्चा में हैं, लेकिन बड़े नाम मैदान में नहीं उतर रहे। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और पूर्व सांसद सुजन चक्रवर्ती चुनाव नहीं लड़ रहे। वे पूरे राज्य में घूम-घूमकर प्रचार कर रहे हैं। युवा नेता शतरूप घोष का नाम भी सूची में नहीं है। उनकी जगह नए चेहरे आगे आए हैं। जैसे दीप्सिता धर, जो एसएफआई की नेता हैं और जेएनयू से शोध कर रही हैं। उन्हें दम दम उत्तर सीट से टिकट मिला है। मीनाक्षी मुखर्जी, जो डीवाईएफआई की अध्यक्ष हैं, उत्तरपाड़ा से लड़ रही हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा अफरीन बेगम शिल्पी को बालीगंज से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा सबीना यास्मिन कलिगंज से, देबलीना हेम्ब्रम रानीबंध से और कई आदिवासी व महिला उम्मीदवार भी हैं। पहली सूची में 27 महिलाएं हैं। नंदीग्राम में सीपीआई के शांति गिरी भाजपा के सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भबानीपुर से श्रीजीब विश्वास और रानीनगर से जमाल हुसैन जैसे नाम भी चर्चा में हैं। लेफ्ट फ्रंट ने कहा है कि हम भारी भरकम नामों की बजाय स्थानीय और साफ छवि वाले लोगों को मौका दे रहे हैं। इन नए नेताओं का काम है युवाओं और छात्रों से जुड़ना। सुजन चक्रवर्ती जैसे अनुभवी नेता अब प्रचार में जुटे हैं। वे कहते हैं कि बंगाल को बचाना है टीएमसी की गलत नीतियों से। ये नेता छोटी-छोटी बैठकें और घर-घर जाकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी युवा वॉलंटियर रील्स और पोस्टर्स बना रहे हैं। इस बार लेफ्ट की रणनीति है कि पुराने अनुभव को नए जोश के साथ मिलाया जाए। लोग देख रहे हैं कि क्या ये युवा चेहरे पुरानी पार्टी को नई पहचान दे पाएंगे।

वामपंथ का एजेंडा: नौकरियां और युवाओं की चिंता

वामपंथी लीडरों का मुख्य एजेंडा इस बार नौकरी सृजन है। वे कहते हैं कि बंगाल में काम नहीं मिल रहा, इसलिए 1.25 करोड़ लोग स्किल्ड या अनस्किल्ड, सब बाहर चले गए। सीपीआईएम के नेता सामिक लाहिरी ने साफ कहा कि युवा वोटरों को वापस लाने के लिए यही मुद्दा सबसे बड़ा है। उनके मेनिफेस्टो में नई नौकरी नीति का खाका तैयार है, जो जल्द जारी होगा। स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और पिछड़े वर्गों का उत्थान भी शामिल है। पूरे राज्य में 70 हजार छोटी बैठकें हो चुकी हैं। उम्मीदवार घर-घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। मोहल्ला स्तर पर चर्चा चल रही है। युवाओं को लक्ष्य बनाकर सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट चलाया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वॉलंटियर रील्स और स्लोगन शेयर कर रहे हैं। लेफ्ट का नारा है "बंगाल बचाओ" टीएमसी की गलत राज से। वे टीएमसी पर भ्रष्टाचार और भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ने की कोशिश है। दरवाजे पर जाकर युवाओं से पूछ रहे हैं कि उनकी पढ़ाई के बाद नौकरी कहां है। आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के गरीब मुहल्लों में फोकस है। महिलाओं और पिछड़ों को भी साथ लाने की कोशिश। इस एजेंडे से लेफ्ट उम्मीद करता है कि 2011 के बाद खोया युवा वोटर फिर लौटेगा। मेनिफेस्टो अंतिम चरण में है। लेफ्ट कहता है कि हमारी नीति अलग है, जो रोजगार पर जोर देगी। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह एजेंडा सिर्फ कागज पर रहेगा या असल में काम करेगा। लेकिन युवा पीढ़ी इस मुद्दे से जुड़ रही है। प्रचार में कोई बड़ा फंड नहीं, सिर्फ विचार वाले वॉलंटियर काम कर रहे हैं। यह तरीका लेफ्ट को अलग पहचान दे रहा है।

पूरा चुनावी समीकरण: टीएमसी, भाजपा और वाम का रोल

2026 का बंगाल चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। टीएमसी सत्ता में है और 291 सीटों पर लड़ रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि वे फिर जीतेंगी। लेकिन वोटर लिस्ट में 1.22 करोड़ नाम कटे हैं, जो विवाद का विषय बना है। मुस्लिम बहुल इलाकों में कई नाम अभी जांच में हैं। भाजपा मजबूत चुनौती दे रही है। अमित शाह ने टीएमसी पर चार्जशीट जारी की। वे कहते हैं कि ममता सरकार में भय और भ्रष्टाचार है। भाजपा ने कई बड़े नामों को टिकट दिया। 57 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार 8000 वोट से कम अंतर था। यहां छोटी सी बदलाव नतीजा पलट सकता है। लेफ्ट और कांग्रेस अलग-अलग लड़ रहे हैं। इससे विपक्षी वोट बंट सकता है। लेफ्ट का रोल अब छोटा हो गया है, लेकिन वे कुछ पॉकेट्स में मजबूत हैं। कांग्रेस मालदा-मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में अपनी ताकत आजमा रही है। टीएमसी को मुस्लिम वोट और महिलाओं का सहारा है। भाजपा हिंदू वोट और विकास के मुद्दे पर जोर दे रही है। लेफ्ट युवा और बेरोजगारी पर फोकस कर रहा है। चुनाव दो चरणों में हैं, पहले चरण में 152 सीटें ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। 2024 लोकसभा में टीएमसी 192 सेगमेंट में आगे थी, भाजपा 90 में। लेफ्ट अभी भी संगठन पर भरोसा कर रहा है। अगर वोटर लिस्ट विवाद बढ़ा तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि टीएमसी मजबूत है, लेकिन भाजपा दबाव बना रही है। लेफ्ट अगर कुछ सीटें जीता तो विपक्षी ध्रुवीकरण में अपनी जगह बना लेगा। कुल मिलाकर समीकरण रोचक है।

आगे का रास्ता: वामपंथ की उम्मीदें और हकीकत

वामपंथ के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन उम्मीद भी है। 34 साल की सत्ता के बाद अब वे निचले स्तर पर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। युवा नेताओं और नौकरी के मुद्दे से कुछ वोटर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि 2021 में शून्य सीटें मिली थीं, इस बार नए चेहरे और घर-घर प्रचार से फर्क पड़ सकता है। लेफ्ट का मानना है कि टीएमसी और भाजपा दोनों से लोग थक चुके हैं। अगर वे "बंगाल बचाओ" का संदेश अच्छे से पहुंचा पाए तो कुछ सीटें निकल सकती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि संगठन कमजोर हुआ है और वोट शेयर बहुत गिरा। कांग्रेस से अलग लड़ना वोट बंटवारे का खतरा बढ़ाता है। फिर भी लेफ्ट का यह प्रयास बंगाल की राजनीति को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। लोग सोच रहे हैं कि क्या पुरानी विचारधारा फिर से जुड़ेगी या नई सच्चाई में वामपंथ छोटी ताकत बनकर रह जाएगा। चुनाव नतीजे बताएंगे कि युवा कितना साथ देते हैं। फिलहाल प्रचार जोरों पर है। वामपंथी नेता कहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। बंगाल की सियासत में वामपंथ हमेशा एक विचार रहा है। अब देखना है कि यह विचार कितना मजबूत साबित होता है। सबकी नजर 4 मई के नतीजों पर है।

तेल पर जंग

मिडल ईस्ट तनाव

रूस का दांव और भारत की परीक्षा

हार्मुज संकट से बढ़ीं वैश्विक कीमतें, रूस ने निर्यात रोका, भारत ने दी राहत-लेकिन क्या महंगाई का तूफान अभी बाकी है?

मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से तेल की कीमतें पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ गई हैं। फरवरी के अंत में शुरू हुए इस संघर्ष ने हार्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित किया जहां से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। ईरान ने जहाजों पर हमले किए और तेल आपूर्ति रोक दी जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। मार्च 2026 के अंत तक कीमतें 108 डॉलर तक चढ़ीं हालांकि कुछ बातचीत से थोड़ी गिरावट आई है। इससे पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ गया है क्योंकि तेल हर चीज की कीमत तय करता है। भारत जैसे देश जो तेल का बड़ा आयातक है उस पर खास असर पड़ा है। सरकार ने बताया कि हार्मुज बंद होने से आपूर्ति में 40 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो तेल 120 डॉलर या उससे ज्यादा हो सकता है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल और एलपीजी महंगे होंगे। कई देशों ने इमरजेंसी स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है लेकिन समस्या जड़ में है। भारत ने भी अपनी रणनीति बदली है ताकि घरेलू बाजार पर बोझ न पड़े। इस तनाव ने न सिर्फ तेल बल्कि गैस की कीमतों को भी प्रभावित किया है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सिर्फ युद्ध का नतीजा है या कुछ और गहरी वजहें हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस स्थिति में हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। भारत ने विविध स्रोतों से तेल खरीदना बढ़ाया है ताकि एक जगह पर निर्भर न रहे। यह सब देखकर लगता है कि तेल की महंगाई सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बड़े बदलाव का संकेत है।

रूस ने पेट्रोल निर्यात पर लगाई रोक

रूस ने अप्रैल 1 से जुलाई 31 तक पेट्रोल का निर्यात बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि यह कदम घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित रखने के लिए उठाया गया है। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों के बाद उत्पादन प्रभावित हुआ है इसलिए निर्यात रोकना जरूरी था। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को गैस सप्लाई रोकने की भी चेतावनी दी है क्योंकि ईरान संकट से ऊर्जा बाजार अस्थिर है। यह फैसला वैश्विक तेल आपूर्ति को और प्रभावित कर रहा है क्योंकि रूस बड़ा उत्पादक है। भारत जैसे देश जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं उन पर असर पड़ सकता है लेकिन अमेरिका ने 30 दिन का विशेष छूट दी है ताकि रूसी तेल खरीदना जारी रहे। रूस का यह कदम सिर्फ घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए है या भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा इस पर बहस चल रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस यूरोप पर दबाव बनाना चाहता है और साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था बचाना चाहता है। इससे वैश्विक तेल की कमी बढ़ी है और कीमतें ऊंची रह गई हैं। भारत सरकार ने रूस से तेल खरीद जारी रखने की बात कही है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह फैसला समय पर लिया गया है या नहीं। रूस का निर्यात बंद होना दुनिया के लिए चुनौती है क्योंकि कई देश इसके भरोसे थे। भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि कोई कमी न हो। यह सब मिलाकर लगता है कि तेल का खेल सिर्फ बाजार का नहीं बल्कि देशों के बीच की रणनीति का भी हिस्सा है। आम लोग इस से महंगाई महसूस कर रहे हैं लेकिन सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं।

> ▶▶ तेल की हर बूंद अब सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष की कहानी बन चुकी है।
> ▶▶ जंग सीमाओं पर है, लेकिन असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है।
> ▶▶ जब ऊर्जा बाजार अस्थिर होता है, तो महंगाई सबसे पहले गरीब की थाली पर हमला करती है।
> ▶▶ तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सिर्फ गाड़ियां नहीं-पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है।
> ▶▶ दुनिया की राजनीति बदलती है, लेकिन उसकी कीमत आम जनता रोज चुकाती है।

भारत सरकार ने लिया राहत का कदम

भारत सरकार ने मिडल ईस्ट तनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर हो गई है और डीजल पर 10 रुपये से घटकर शून्य कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम आम लोगों को महंगाई से बचाने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल कंपनियों को सपोर्ट देने का फैसला किया ताकि कीमतें न बढ़ें। सरकार ने 25 करोड़ लीटर से ज्यादा स्टॉक रखा है जो 7-8 हफ्ते का है। रूस से तेल खरीद जारी है और अमेरिका ने भी 30 दिन की छूट दी है। इससे एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई बनी रहेगी। सरकार का कहना है कि विविध स्रोतों से तेल लाने से एक जगह पर निर्भरता कम हुई है। हार्मुज जलडमरूमध्य पर 40 प्रतिशत आयात प्रभावित हो सकता है लेकिन अन्य रास्तों से सामान आ रहा है। यह उपाय जनता को तुरंत राहत दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर हैं। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ राहत है या चुनावी समय को देखकर लिया गया कदम। सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और एथनॉल मिश्रण से भी तेल बचत हो रही है। यह सब देखकर लगता है कि सरकार ने समय रहते तैयारी की है। विपक्ष इसे पर्याप्त नहीं बता रहा लेकिन तथ्य यह है कि आम आदमी को फायदा हो रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह रणनीति काम कर रही है।

योगी आदित्यनाथ की सकारात्मक प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल महंगा है लेकिन भारत में स्थिति नियंत्रण में है। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ की और कहा कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग न करें। योगी जी ने स्पष्ट किया कि अगर युद्ध लंबा चला तो असर हो सकता है लेकिन अभी सब ठीक है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का शुक्रिया क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला जनता के हित में है। उन्होंने बताया कि कई देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं लेकिन भारत में नियंत्रित हैं। यह प्रतिक्रिया सत्ताधारी दल की तरफ से आश्वासन दे रही है। योगी जी की बात से लगता है कि सरकार जनता के साथ है और कोई राजनीतिक खेल नहीं बल्कि सच्ची राहत दे रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह सब मिलाकर भाजपा नेतृत्व का संदेश साफ है कि चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। योगी की यह प्रतिक्रिया आम लोगों को भरोसा दिला रही है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिडल ईस्ट संकट पर चिंता जताई और कहा कि भारत में ईंधन और एलपीजी की समस्या आ सकती है। उन्होंने संसद में बहस की मांग की और सरकार पर आरोप लगाया कि विदेश नीति कमजोर होने से यह स्थिति बनी। राहुल ने चेतावनी दी कि रुपये का कमजोर होना और तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। जयराम रमेश ने भी सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने संसद में तेल कीमतों पर हंगामा किया और कहा कि सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या एक्साइज ड्यूटी घटाना सिर्फ जनता को राहत है या चुनावी रणनीति। राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी समस्या आ रही है इसलिए तैयारी करो। विपक्ष का कहना है कि रूस से तेल खरीदना अच्छा है लेकिन कुल मिलाकर स्थिति पर नजर नहीं रखी गई। यह बहस दिखाती है कि राजनीतिक दलों में मतभेद है लेकिन दोनों पक्ष जनता के हित की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कदम पर्याप्त हैं जबकि विपक्ष और तैयारी चाहता है।

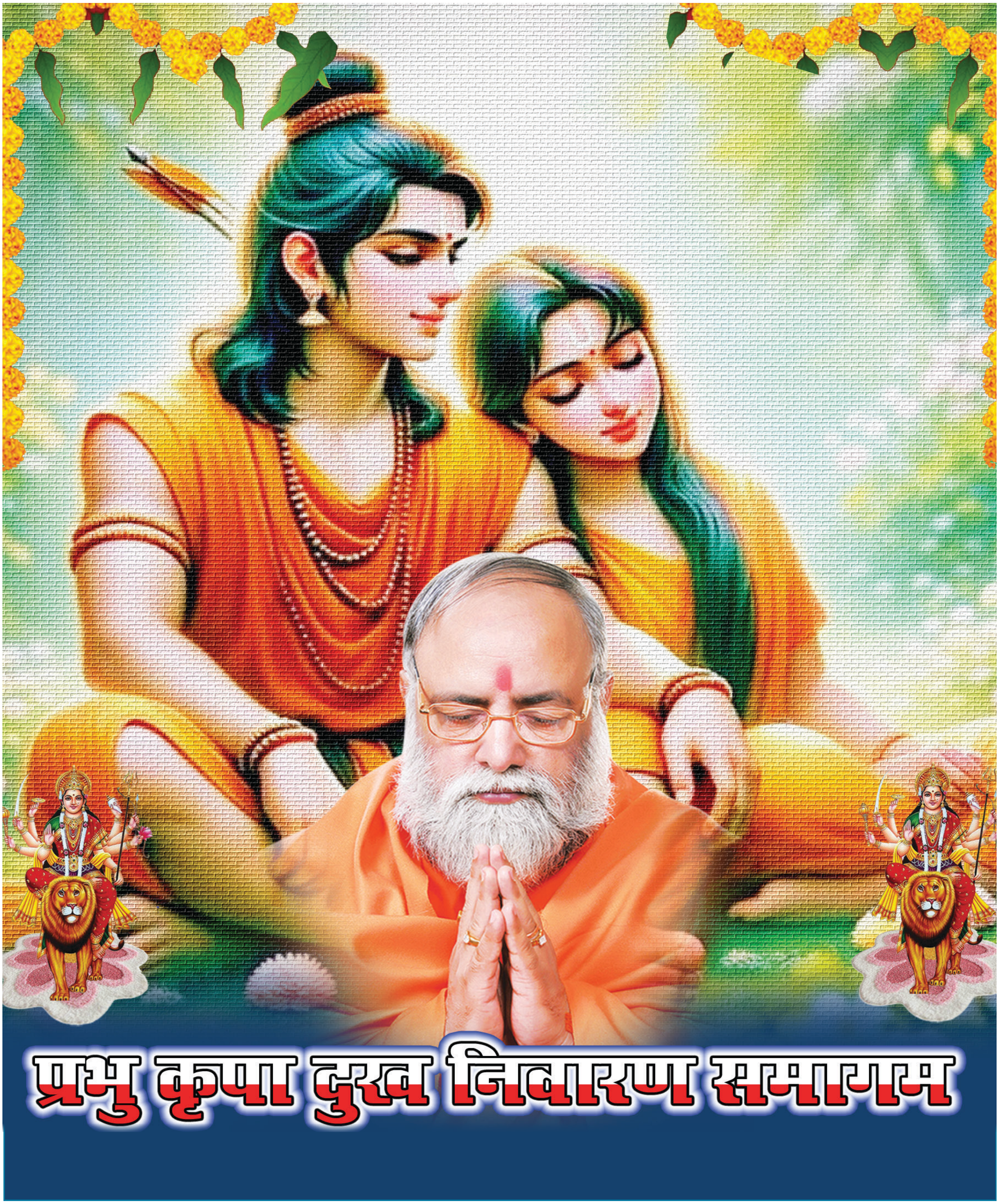
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY
Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO
ARITIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

Arihanta Industries

ORDER ONLINE @ :

amazon   arihanta.in